Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 10
अंक : 251
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
बुधवार, 17 सितम्बर, 2025

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर ... 4 प्रधानमंत्री का संवाद देश और दिलों को जोड़ता .. 7 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के बाद ...

संक्षिप्त न्यूज

संत कबीर के नाम पर यूपी में स्थापित होंगे वस्त्र एवं परिधान पार्क : सीएम योगी

लखनऊ **(एजेंसी)**। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निजी निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए विभिन्न जिलों में वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पारंपरिक हथकरघा और वस्त्र उत्पादों की समृद्ध धरोहर वाला राज्य है, जिसकी क्षमता का सही उपयोग होने पर प्रदेश को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान दिलाई जा सकती है।

एक बयान में उन्होंने कहा कि वर्तमान में वस्त्र एवं परिधान का वैश्विक बाजार वर्ष 2030 तक 2, 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है और भारत इसमें आठ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ सबसे तेज़ी से बढ़ते देशों में है। ऐसे परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की भागीदारी इस क्षेत्र में निर्णायक सिद्ध हो सकती है। योगी ने कहा, "प्रस्तावित योजना को महान संत कबीर के नाम पर समर्पित किया जाएगा।" उन्होंने कहा, "संत कबीर ने अपने जीवन दर्शन में श्रम, सादगी और आत्मनिर्भरता को सर्वोपरि माना और यही भाव इस योजना का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस योजना के माध्यम से निवेश, उत्पादन और रोजगार के नए अवसरों के साथ-साथ परंपरा और आधुनिकता का संतुलन स्थापित होगा।"

बैठक में प्रस्तुत विवरण के अनुसार, वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष वस्त्र एवं परिधान निर्यातक राज्यों में शामिल है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश से लगभग 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ, जो देश के कुल वस्त्र एवं परिधान निर्यात का लगभग 9.6 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन कार्यक्रमों से जनता से जुड़ने की कोशिश करेगी भाजपा, मिलेगी बड़ी सौगात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर भाजपा बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। 17 सितंबर को पूरे देश में 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग एक लाख स्वास्थ्य कैम्प लगाए जाएंगे जिसमें लोगों का इलाज करने के साथ साथ उन्हें केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी दी जाएगी। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेश के धार जिले से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और महिलाओं से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री के गृहराज्य गुजरात में सुबह-सुबह मंदिरों में पूजा-पाठ के कार्यक्रम रखे गए हैं तो पीएम के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में रक्तदान शिविर आयोजित कर उन्हें शुभकामनाएं दी जाएंगी। इसके अलावा एक पखवाड़े तक चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये पार्टी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेगी।

गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाए जाने की पूरी तैयारी की गई है। सीआर पाटिल ने इन कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है। इनके अंतर्गत गुजरात के विभिन्न मंदिरों में पूजापाठ की योजना

बनाई गई है। मंदिरों के साथ बाजारों और बस्तियों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सेवा पखवाड़े में जगह-जगह मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी।

पार्टी बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर हर विधानसभा में विशेष स्वास्थ्य कैम्प लगाएगी। इसमें लोगों को मुफ्त उपचार के साथ-साथ केंद्र सरकार की आयुष्मान जैसी मुफ्त स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अब तक केंद्र और बिहार सरकार की विशेष सेवाओं का लाभ ले चुके लोगों से संपर्क किया जाएगा। जिन लोगों को अब तक केंद्र सरकार की आयुष्मान जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, भाजपा कार्यकर्ता उन्हें इन योजनाओं का लाभ लेने के उपाय बताएंगे।

पांच बड़े अस्पतालों के साथ विभिन्न योजनाओं की शुरुआत

देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 75 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा ने सत्ता हासिल करने के साथ ही दिल्ली को विकसित राजधानी के रूप में परिवर्तित करने का सपना लोगों को दिखाया था। पीएम के जन्मदिवस पर इसी को थीम बनाया गया है। बुधवार को दिल्ली को पांच नए अस्पताल मिलेंगे। 75 ड्रोन उड़ाकर मोदी को जन्मदिन की बधाई दी जाएगी।

दिल्ली की सार्वजनिक बस सेवा को बेहतर बनाने के लिए सौ नई बसों को बुधवार को ही सड़कों पर उतारा जाएगा। इसके अलावा अंग प्रत्यारोपण की नई सुविधाएं देकर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बड़ी सौगात दी जायेगी। पीएम की अब तक की जीवन यात्रा पर विशेष प्रदर्शनी के साथ दिल्ली के स्कूली छात्रों की विशेष चेन अपने अलग अंदाज में मोदी को जन्मदिन की बधाई देंगे।

मोदी सरकार का नशा मुक्त भारत का संकल्प

अमित शाह बोले- 2047 तक खत्म होगा खतरा

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश से सभी प्रकार के नशीले पदार्थों का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल (एएनटीएफ) के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ कार्रवाई के पैमाने में बदलाव किया जाए ताकि आने वाले दिनों में और अधिक सफलताएँ मिलें।

अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने 2047 में एक महान भारत के निर्माण की संकल्पना प्रस्तुत की। एक ऐसा भारत जो पूर्णतः विकसित होगा। अगर हमें ऐसा भारत बनाना है, तो अपनी युवा पीढ़ी को नशे से बचाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी महान राष्ट्र की संकल्पना, उसकी नींव उस देश की युवा पीढ़ी होती है। अगर हमारी आने वाली पीढ़ियाँ खोखली हो जाएँगी, तो देश भटक जाएगा... दुर्भाग्य से, वे दोनों क्षेत्र जहाँ से दुनिया भर में नशे की आपूर्ति होती है, हमारे नज़दीक ही हैं... इसलिए यही समय है कि हम इसके खिलाफ मजबूती से लड़ें।

शाह ने कहा कि तीन तरह के कार्टेल होते हैं, एक वो कार्टेल जो देश के सभी एंट्री पॉइंट्स पर काम करता है, दूसरा वो कार्टेल जो एंट्री पॉइंट से राज्य तक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्टेल है और तीसरा वो कार्टेल जो राज्यों में पान की दुकान या गली के नुक्कड़ पर ड्रग्स बेचने तक काम करता है। इन तीनों तरह के कार्टेल्स पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। मेरा मानना ??है कि ऐसा तभी हो सकता है जब यहां बैठे लोग तय कर लें कि ये लड़ाई हमारी लड़ाई है।

अमित शाह ने कहा कि भगोड़ों का निर्वासन और प्रत्यर्पण, ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब समय आ गया है कि जो लोग विदेश में बैठकर यहाँ नशे का कारोबार कर रहे हैं, उन्हें हमारे कानून के दायरे में लाया जाए। सीबीआई ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी एएंडटीएफ अध्यक्षों से अनुरोध करता हूँ कि वे सीबीआई निदेशक से संपर्क करें और प्रत्यर्पण के लिए एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करें, जो न केवल नशे, आतंकवाद, गिरोहों, बल्कि हर चीज़ के लिए उपयोगी हो। यह बहुत ज़रूरी है और जिस तरह प्रत्यर्पण ज़रूरी है, उसी तरह व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ निर्वासन भी ज़रूरी है।

कर्नाटक के राज्यपाल ने विधेयक लौटाया, झीलों का बफर जोन कम करने पर मांगा स्पष्टीकरण

बंगलूरू। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य में झीलों या तालाबों के आसपास के बफर जोन के आकार को कम करने वाला विधेयक सरकार को लौटा दिया है और सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा के दोनों सदनों में पारित कर्नाटक टैंक संरक्षण और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक में जलाशयों के क्षेत्रफल के आधार पर झीलों के बफर जोन को कम करने का प्रस्ताव है।

राज्यपाल ने विधेयक पर मांगा स्पष्टीकरण

राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा है कि उठाए गए मुद्दों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण लेना जरूरी है, और यह भी जानना जरूरी है कि इस संशोधन का कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। राज्यपाल कार्यालय से सरकार को भेजे एक पत्र में

कहा गया है कि, 'इस संबंध में सही स्पष्टीकरण के साथ फाइल को फिर से प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को वापस कर दिया जाए।' राज्यपाल ने सरकार को भेजे अपने पत्र में ये भी कहा कि बंगलूरू टाउन हॉल एसोसिएशन ने उनके कार्यालय से इस विधेयक को मंजूरी न देने का अनुरोध किया है।

एसोसिएशन ने चिंता व्यक्त की है कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार, वर्तमान झील बफर जोन 30 मीटर ही अपर्याप्त है, और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन के लिए करीब 300 मीटर बफर जोन होना चाहिए। एसोसिएशन ने कहा है कि बफर जोन को बढ़ाया जाना चाहिए, न कि घटाया जाना चाहिए। एसोसिएशन के अनुसार, 'यह संविधान और स्थापित कानून का उल्लंघन है, और प्रत्येक नागरिक के लिए हानिकारक है, यह नागरिकों के जल सुरक्षा और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को प्रभावित करता है।' राज्यपाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस संशोधन के असर के बारे में न तो विशेषज्ञ समिति से और न ही जनता से परामर्श किया है।

टीटीवी दिनाकरण ने पलानीस्वामी पर साधा निशाना, गठबंधन की किसी भी संभावना को किया खारिज

अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी की कड़ी आलोचना करते हुए दावा किया कि 2026 के चुनावों के बाद, पलानीस्वामी बीच सड़क पर खड़े रह जाएँगे। तंजावुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, दिनाकरन ने कहा, 'एडप्पादी दावा करते हैं कि उन्होंने कृतज्ञता दिखाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन यह 'शैतान द्वारा शास्त्र पढ़ने' से कम नहीं है। पलानीस्वामी को भाजपा ने नहीं, बल्कि उन 122 विधायकों ने बचाया था जो संकट के दौरान कूवथुर में ठहरे हुए थे।'

दिनाकरन ने कहा कि पलानीस्वामी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया, कि वह झूठ का पुलिंदा हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि 2026 के चुनावों में तमिलनाडु की जनता पलानीस्वामी को पूरी तरह से नकार देगी। पार्टी के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा, 'एएमएमके के एडप्पादी के साथ गठबंधन करने की कोई संभावना नहीं है।' उनके अनुसार, पलानीस्वामी ने 'दो पत्ती' चुनाव चिन्ह और धनबल का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार के साथ गठबंधन किया है, लेकिन उनका वोट शेयर 20 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह जाएगा।

दिनाकरन ने कहा कि एडप्पादी को कृतज्ञता के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है–यह शैतान द्वारा शास्त्रों का जाप करने जैसा है। वह कोई डॉन नहीं हैं। हर समस्या के लिए पलानीस्वामी स्वयं ज़िम्मेदार हैं। वह हथेली पर रखे आंवले की तरह हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु प्रमुख नैनार नागेंद्रन की भी आलोचना करते हुए कहा, 'नागेंद्रन अपने बयान बदलते रहते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार करूँगा, और न ही मैंने नागेंद्रन से ऐसा कभी कहा।'

इससे पहले 7 सितंबर को, भाजपा प्रमुख नैनार नागेंद्रन ने कहा था कि एएमएमके के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) छोड़ने के लिए वह ज़िम्मेदार नहीं हैं, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह टीटीवी दिनाकरन को पकड़ने के लिए तैयार हैं।

धर्मांतरण कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जवाब मांगा, छह हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कई राज्यों से उनके धर्मांतरण रोधी कानूनों पर जवाब मांगा है। कोर्ट में दायर याचिकाओं में इन कानूनों की वैधता को चुनौती दी गई है और उन पर रोक लगाने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने साफ किया कि राज्यों के जवाब आने के बाद ही इन कानूनों पर रोक लगाने की अर्जी पर विचार होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं को इसके बाद दो हफ्ते का समय दिया गया है ताकि वे राज्यों की दलीलों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकें। इस मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष के वरिष्ठ वकील सी. यू. सिंह को याचिका संशोधित करने की भी अनुमति दी है, ताकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किए गए 'कड़े बदलावों' को चुनौती में शामिल किया जा सके।

ममता बनर्जी का चुनाव आयोग से तीखा सवालः लोग एसआईआर के लिए बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे?

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए जन्म प्रमाण पत्र की उपलब्धता में आने वाली कठिनाइयों की ओर इशारा किया और संस्थागत प्रसव की पिछली सीमाओं का हवाला दिया। यह ऐसे समय में आया है जब चुनाव आयोग आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू करने की योजना बना रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में नई वुडबर्न 2 बिल्डिंग 'अनन्या' का अनावरण करते हुए कहा कि लोग एसआईआर के लिए जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त करेंगे? उस समय यह संभव नहीं था, क्योंकि संस्थागत प्रसव प्रचलित नहीं था।

इससे पहले 11 सितंबर को, भाजपा नेता दिलीप घोष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को एक 'अच्छी प्रथा' बताया और कहा कि चुनाव आयोग को बिहार में इसे करने से पहले पश्चिम बंगाल में यह अभ्यास करना चाहिए था। एएनआई से बात करते हुए, घोष ने कहा, 'सबसे पहले, यह बंगाल में किया जाना चाहिए था, लेकिन यह अच्छी बात है कि बिहार में यह प्रक्रिया अपनाई गई है। बंगाल में भी इसे लागू किया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है।'

हालांकि, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने अभी तक राज्य में एसआईआर के आयोजन की तारीखों की घोषणा नहीं की है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को कहा था कि इस पर फैसला लिया जाएगा। सीईसी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 'तीनों चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में एसआईआर कब लागू किया जाएगा।' ममता बनर्जी ने राज्य की वित्तीय समस्याओं, खासकर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे और परियोजनाओं के वित्तपोषण को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पश्चिम बंगाल को जीएसटी मुआवजे के रूप में 20,000 करोड़ रुपये नहीं मिल रहे हैं और विभिन्न पहलों के लिए धन जुटाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाय

आंबेडकर आंदोलन के नेता और लोग भाग लेंगे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपने के लिए देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से बौद्ध अनुयायी मैदान में उतर आए हैं। अब, आंबेडकर आंदोलन के कई राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और साथ ही बौद्ध अनुयायी इस मुद्दे पर एक साथ आए हैं। वे 14 अक्टूबर को मुंबई के वीर जीजामाता भोसले उद्यान से आज़ाद मैदान तक एक विशाल मार्च निकालेंगे। पूरा आंबेडकर बौद्ध समुदाय महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए एकजुट हो गया है और अब मैदान में उतरेगा, आंबेडकर आंदोलन के सभी दलों के नेताओं ने आज जानकारी दी। कई लोगों ने गरवारे क्लब में इस आंदोलन के बारे में अपनी स्थिति बताई। इस अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठावले ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी और कहा कि हजारों बौद्ध भाई इस रैली में भाग लेंगे यदि कलेक्टर हिंदू है, तो वह अध्यक्ष है। इसलिए, यह महाविहार पूरी तरह से बौद्धों के नियंत्रण में नहीं है। इसलिए, महाबोधि महाविहार प्रबंधन अधिनियम 1949 (बीटीअधिनियम) को निरस्त करने की मांग जोर पकड़ रही है। यह मांग की जा रही है कि महाबोधि महाविहार ट्रस्ट के सभी 9 सदस्य और अध्यक्ष बौद्ध होने चाहिए। प्रत्येक धर्म के धार्मिक स्थल उस धर्म के ट्रस्ट के अधीन हैं। इस आधार पर, बौद्ध बुद्ध विहार बौद्धों के नियंत्रण में क्यों नहीं है? यह सवाल नेताओं द्वारा पूछा गया था।

इस बीच, गरवारे क्लब में इस बारे में जानकारी देने के लिए रामदास आठवले, प्रा जोगेंद्र कवाड़े, डॉ. राजेंद्र गवई, नाना इंदिस, सांसद चंद्रकांत हंडोरे, सांसद वर्षा गायकवाड़, अर्जुन डांगले, राजू वाघमारे; जयदेव गायकवाड़, अविनाश महातेकर, राम पंडागले, भाई गिरकर, अक्षय दिलीप आंबेडकर, तानसेन ननावरे, काकासाहेब खंबालकर, दिलीप जगताप, सुनील निर्भवने, सुरेश केदारे, नितिन मोरे, मिलिंद सुर्वे, विलास रूपवते, रवि गरुड़, आकाश लामा, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संयोजक भदंत आयुपाल; भदंत शांतिरत्न; भदंत लामा एवं अन्य उपस्थित थे।

अनधिकृत कॉल सेंटर पर पुलिस का छापा

अमेरिकन नागरिकों से ठगी करने वाले गिरफ्तारी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई क्राइम ब्रांच सेल 12 ने एक फर्जी कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपी अनधिकृत कॉल सेंटर चलाकर अमेरिकन नागरिकों से ठगी कर रहा था। पुलिस ने आरोपियों से इस अपराध में इस्तेमाल की गई सामग्री जब्त की है। यह अनधिकृत कॉल सेंटर 704/705, 7वीं मंजिल, विहान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वालभट्ट रोड, जवाहर फाटका के पास, गोरेगांव में चल रहा था। आरोपी अमेरिकी नागरिकों को greeksquad ke mac cafee एंटीवायरस के साथ अपने कंप्यूटर को नवीनीकृत करने के लिए मेल भेज रहा था और उन्हें टोल-फ्री नंबर भेज रहा था। उसके बाद, जब इस नंबर पर एक अमेरिकी नागरिक का सॉफ्टवेयर कॉल आता था, तो वे

अमेरिकी नागरिक को एंटीवायरस को नवीनीकृत करने के लिए 250 से 500 डॉलर का गिफ्ट कार्ड खरीदवाते थे इसलिए, पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा और 15 कंप्यूटर, 10 लैपटॉप और 20 मोबाइल फोन आदि सहित फोन, कंप्यूटर और अन्य प्रयुक्त उपकरण जब्त कर लिए और 2 कॉल सेंटर संचालकों और मालिकों, 1 मैनेजर, 10 टेली-कॉलर एजेंटों को उक्त स्थान से हिरासत में ले लिया।

इन आरोपियों के खिलाफ वनराई पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 66 (सी) के साथ-साथ दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 3(1), 42(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

निकाय चुनाव को लेकर एनसीपी शरद की SEC से मांग, कहा- सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया जाए पालन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के राजनीतिक दल सतर्क हो गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-शरद) ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग निकाय चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तत्काल पालन करें। पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने कहा कि यदि वे एक बार फिर विफल होते हैं, तो कोर्ट को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह 2022 से रुके राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों को बिना किसी और विस्तार के 31 जनवरी 2026 तक पूरा करे। चुनाव न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी।

एक्स पर एक पोस्ट में एनसीपी के प्रवक्ता क्रैस्टो ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और एसईसी ने पहले छह मई को जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनादर किया था। इसमें चार सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों को अधिसूचित करने और चार महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया गया था।

एनसीपी प्रवक्ता ने कहा कि अब सर्वोच्च निकाय ने राज्य चुनाव आयोग को बिना किसी और विस्तार के 31 जनवरी 2026 तक की समय सीमा दी है। भाजपा नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार और ईसीआई को तुरंत आदेश का पालन करना चाहिए। अगर वे एक बार फिर इसे लागू करने में विफल रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या भाजपा चुनावों से डरती है? उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार समय पर चुनाव कराना चाहिए, अन्यथा भाजपा के प्रभाव का संदेह और मजबूत होता जाएगा।

कोर्ट ने क्या कहा

महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि जिला परिषदों, पंचायत समितियों और सभी नगर पालिकाओं सहित सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक करा लिए जाएंगे। राज्य और राज्य चुनाव आयोग को इसके बाद कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र में नगरपालिका परिषदों, नगर पंचायतों और नगर निगमों के सदस्यों के चयन के लिए अंतिम बार 2017 में स्थानीय चुनाव हुए थे।

महायुति सरकार पर आदित्य ठाकरे का हमला

'मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खत्म किया जा रहा है'

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि महायुति सरकार ऐप-आधारित बस और बाइक-टैक्सी सेवाओं को मंजूरी देकर मुंबई की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) ने ओला, ऊबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को मुंबई महानगर क्षेत्र में बाइक टैक्सी चलाने के लिए अस्थायी लाइसेंस की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 1.5 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 15 रुपये तय किया गया है।

BEST बसों को भी मिले आर्थिक सहायता- आदित्य

आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया कि बाइक टैक्सियों के लिए क्या नियम तय किए गए हैं। उन्होंने कहा, 'चाहे बाइक टैक्सी हों या सिटी फ्लो बसें, भाजपा-शिवसेना सरकार निजीकरण कर रही है। यह मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खत्म कर रही है।' पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार को ँएऊ बसों के लिए भी वही उत्साह दिखाना चाहिए जो वह बाइक टैक्सियों के लिए दिखा रही है, और ँएऊ को आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

राज्य के परिवहन मंत्री पर भी बरसे आदित्य ठाकरे

उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर भी निशाना साधा। ठाकरे ने दावा किया कि जुलाई में रैपिडो ऐप से राइड बुक कर बाइक टैक्सियों की गैरकानूनी सेवाओं को उजागर करने वाला ड्रामा रचा गया था, जबकि रैपिडो ने मंत्री के रिश्तेदार के कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया था। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि मुंबई की प्रमुख पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा ँएऊ को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है। 'निजी बस ऑपरेटरों की भरमार हो गई है, जबकि BEST का बेड़ा कम किया जा रहा है, किराए बढ़ाए जा रहे हैं और बस डिपो बेचे जा रहे हैं।'

शिवसेना यूबीटी नेता ने आरोप लगाया, 'भाजपा सरकार मुंबई की सड़कों और ट्रैफिक को बिगाड़ रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महंगा और लोगों की पहुंच से बाहर कर रही है, ताकि मुंबई की आर्थिक ताकत कमजोर हो जाए।'

अब और मोहलत नहीं! महाराष्ट्र निकाय चुनाव में देरी पर एससी खफा, कहा- 2026 तक कराएं मतदान

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को राज्य में 31 जनवरी, 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने राज्य के अधिकारियों को 10 अक्टूबर तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पारित किया। शीर्ष अदालत ने राज्य चुनाव आयोग पर 6 मई को स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा चार सप्ताह के भीतर करने और चार महीने के भीतर चुनाव कराने के स्पष्ट आदेश के बावजूद तुरंत कार्रवाई न करने के लिए असंतोष व्यक्त किया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा, 'क्या चुनाव पहले ही हो चुके हैं?' उन्होंने मई के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें चार महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया गया था। महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा कि प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि परिसीमन पूरा हो चुका है और राज्य चुनाव आयोग कुछ अतिरिक्त समय मांग रहा है, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में एक अंतरिम आवेदन भी दायर किया गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सवाल किया, 'हम आपको जनवरी तक का समय क्यों दें?'

एक अन्य वकील ने बताया कि 29 नगर निगम हैं और पहली बार एक साथ चुनाव हो रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'आपकी निष्क्रियता अक्षमता दर्शाती है... कृपया मौखिक रूप से कारण स्पष्ट करें।' वकील ने आगे कहा कि उनके पास वर्तमान में 65,000 ईवीएम मशीनें हैं और उन्हें 50,000 और मशीनों की आवश्यकता है, जिसके लिए ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं। न्यायालय ने अब महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव कराने के लिए एक नई समय सीमा निर्धारित करते हुए एक अतिरिक्त विस्तार की अनुमति दे दी है, तथा कहा है कि अब और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

अनुवादकों की सूची तैयार करने हेतु आवेदन

मुंबई। प्रशासनिक, विधि, चिकित्सा, राजस्व, शैक्षणिक, अभियांत्रिकी आदि विभिन्न विषयों में 'अंग्रेजी पाठ का मराठी में और मराठी पाठ का अंग्रेजी में अनुवाद' करने में सक्षम अनुवादकों की सूची शुल्क के आधार पर तैयार की जानी है। इसके लिए, मोदी पाठ का अंग्रेजी और मराठी में अनुवाद, अंग्रेजी से मराठी और मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद करने में सक्षम अनुवादकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस संबंध में नियम, शर्तें और अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कृपया भाषा निदेशालय की वेबसाइट directorate.marathi.gov.in देखें। इच्छुक पक्ष मूल प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ 17 अक्टूबर 2025 तक भाषा निदेशालय, नया प्रशासनिक भवन, 5वीं मंजिल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051 को आवेदन भेजें, ऐसा भाषा निदेशक श्रीमती विजया डोनिकर ने अपील की है।

वास्कर परिवार ने 112 साल पुरानी '21 दिवसीय गणेशोत्सव परंपरा' को संजोया

मुंबई। सानपाड़ा गांव का वास्कर परिवार 112 साल से 'एक परिवार, एक गणपति' की '21 दिवसीय गणेशोत्सव' परंपरा को संजोए हुए है। दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे और उनके माता-पिता की प्रेरणा से यह पुश्तैनी परंपरा जारी है, जिसमें 80 प्रतिशत सामाजिक कार्य और 20 प्रतिशत राजनीति है। अब इस विरासत को पूर्व नगरसेवक सोमनाथ वास्कर और कोमल वास्कर आगे बढ़ा रहे हैं। यहां एक ही इमारत में रहने वाले करीब 75 परिवार 21 दिनों तक गणपति की पूजा करते हैं। सोमनाथ वास्कर के परदादा बालू वास्कर ने अपने दादा गणपत वास्कर के लिए मन्नत मांगी थी। तब से वास्कर परिवार में यह गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। चौथी पीढ़ी ने भी पारिवारिक एकता और गणेशोत्सव की परंपरा को कायम रखा है। इसी वजह से यह परिवार सानपाड़ा गांव में प्रसिद्ध है। हर दिन महाप्रसाद और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। पिछले 21 दिनों से विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग गणेश दर्शन के लिए आ रहे हैं। यह जानकारी पूर्व नगरसेवक सोमनाथ वास्कर ने दी।

इस बीच, सानपाड़ा गाँव में गणपति बप्पा को विदाई देने के लिए 21 वें दिन भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है। उन्होंने बताया कि अब आखिरकार 21 दिनों के बाद बप्पा को विदाई दे दी गई है।

मध्य रेल

ई-टेंडर निविदा क्र.

34-2025-LL-DAE-CPW dt. 15/09/2025

कार्य का नामः नागपुर मंडल के दहेगाँव और छोटीपडोली स्टेशनों पर लूप लाइन उन्नयन से संबंधित सिग्नलिंग कार्य। **अनुमानित लागतः** ₹ 6947603.73. **बयाना रकमः** ₹139000/-. **निविदा बंद करने की तिथि तथा समय** : **13/10/2025** को **15.00** बजे तक है। विस्तृत जानकारी रेलवे वैबसाइट सूचना **www.ireps.gov.in** पर देखें।

मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर (दक्षिण) नागपुर

Sai/NGP/200

अपने जानवरों को रेल लाइन से दूर रखे

अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा अहमदनगर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड में नहीं होगा बदलाव

मुंबई। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब अहिल्यानगर कर दिया गया है। यह निर्णय लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर के सम्मान में लिया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

पिछले सप्ताह महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद स्टेशन का नाम बदलने की अधिसूचना जारी की थी। इससे पहले राज्य सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम भी बदलकर अहिल्यानगर जिला कर दिया था।

सेंट्रल रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया, पहले अहमदनगर के नाम से जाना जाने वाला स्टेशन अब आधिकारिक रूप से अहिल्यानगर कहलाएगा। स्टेशन कोड में कोई बदलाव नहीं होगा और यह पहले की तरह ही ँउ रहेगा।

पिछले महीने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर स्टेशन का नाम बदलने की मांग की थी, ताकि शहर के नए नाम से मेल खा सके। कई संगठनों और नागरिकों ने भी लंबे समय से अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की मांग उठाई थी।

राज्य में बीड़ी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी के प्रति सरकार सकारात्मक- श्रम मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

श्रम मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर ने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र में बीड़ी श्रमिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं और उन्हें नियमों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, इस पर सरकार सकारात्मक है।

पूर्व विधायक नरसय्या आदम के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य बीड़ी श्रमिक संघ, नव महाराष्ट्र बीड़ी श्रमिक संघ, भारतीय मजदूर संघ और कामगार सेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में बीड़ी उद्योग के श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर श्रम मंत्री एडवोकेट फुंडकर से मुलाकात की। इस अवसर पर, मंत्री एडवोकेट फुंडकर ने इन प्रतिनिधिमंडलों को आश्वासन दिया। बीड़ी श्रमिक संघ का कहना है कि राज्य के विभिन्न जिलों में बीड़ी श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी अपर्याप्त है। इसके लिए श्रम आयुक्त ने मंत्री एडवोकेट फुंडकर को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि अगले महीने बीड़ी कारखाना मालिकों के साथ बैठक करके इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। साथ ही, केंद्र सरकार ने अब बीड़ी और उसमें इस्तेमाल होने वाले पत्तों पर जीएसटी की दर कम कर दी है, जिससे बीड़ी उद्योग को लाभ होगा। मंत्री एडवोकेट फुंडकर ने यह भी कहा कि इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या इससे बीड़ी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का मुद्दा हल हो सकता है।

केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, बीड़ी श्रमिकों का वेतन बैंक में जमा होता है। श्रमिक संघ की माँग है कि यह वेतन नकद में मिले। इस संबंध में विधि एवं न्याय विभाग को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा और बीड़ी श्रमिकों को नकद वेतन देने पर विचार किया जाएगा, श्रम मंत्री एडवोकेट फुंडकर ने इस अवसर पर कहा।

इस बैठक में श्रम विभाग के प्रधान सचिव आई.ए. कुंदन, श्रम आयुक्त एच.पी. तुम्मोड़, पुणे के अतिरिक्त श्रम आयुक्त बी.वी. वाघ और श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मध्य रेल

सोलापुर मंडल

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, सामान्य, मध्य रेल, सोलापुर, निम्नलिखित कार्य के लिए ख्याति प्राप्त, अनुभवी और लाईसेंसधारी विद्युत ठेकेदारों से रेलवे की ई-प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित करते हैं। **ई-निविदा सूचना क्र.: सोला/वि/नि/2025/16. कार्य का नामः** सोलापुर डिवीजन में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करके एलटी प्रणाली को मजबूत करने के संबंध में विद्युत सामान्य सेवा भाग का कार्य। **कार्य की लागतः** ₹ 2,19,43,301.28. **बोली प्रतिभूतिः** ₹2,59,700/-. **कार्य पुरा करने की अवधिः** 12 माह। **निविदा प्रस्ताव की वैधताः** 60 दिन। **वेबसाइट पर निविदा बंद करने की तिथि और समयः** दि. **09/10/2025** को **15.00 बजे।** बोली प्रतिभूति राशि की रकम का भुगतान ई-पेंमेंट द्वारा वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर करना है।

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (सा) सोलापुर

Sai/SUR/55

अपने जानवरों को रेल लाइन से दूर रखे

पश्चिम रेलवे

विभिन्न कार्य

मंडल रेल प्रबंधक (पश्चिम रेलवे), पश्चिम रेलवे, छठी मंजिल, इंजीनियरिंग विभाग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400008, आमंत्रित करते हैं- **क्रमांकः** 1. **निविदा सूचना संख्याः** बीसीटी-25-26-224, दिनांक 12.09.2025। **कार्य और स्थानः** सांताक्रूज़ से विरारः असामान्य घटनाओं से बचने के लिए आरसीसी सदस्यों और सेवा भवन की छत की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण। **कार्य की अनुमानित लागतः** 1,52,43,884.19/- **अग्रिम जमाः** 2,26,200/-। **क्रमांकः** 2. **निविदा सूचना संख्याः** बीसीटी-25-26-225, दिनांक 12.09.2025। **कार्य और स्थानः (1)** माटुंगा रोड रेलवे कॉलोनी की सड़क और जल निकासी व्यवस्था की मरम्मत। (2) मुंबई सेंट्रल (कारशेड): मुंबई सेंट्रल कारशेड में विभिन्न आवश्यक मरम्मत कार्य। (3) मुंबई सेंट्रल (कारशेड): लीक हो रही छत की शीट, वैली गटर, डाउनटेक पाइप और टूटी हुई साइड शीट को बदलना। (4) महालक्ष्मीः महालक्ष्मी खेल मैदान में विविध मरम्मत कार्य। **कार्य की अनुमानित लागतः** 6,12,36,582.05 **ब्याज राशिः** 4,56,200/- **दोनों निविदाएँ जमा करने की तिथि और समयः** 10.10.2025, 15:00 बजे तक। **दोनों निविदाएँ खोलने की तिथि और समयः** 10.10.2025 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएँ।

0598

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित

विद्यार्थी 'विकसित भारत संवाद' ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में भाग लें- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अपील

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने महाविद्यालयीन विद्यार्थियों से इन गतिविधियों में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विकसित भारत का सपना देखा है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत महोत्सव जन्मदिन के अवसर पर, भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी से पहले देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से 'विकसित भारत 2047' पहल लागू की जा रही है। इसके माध्यम से देश आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और प्रशासनिक विकास प्राप्त कर भारत को एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में

स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। युवाओं की भागीदारी से 'विकसित भारत दूत युवा संपर्क' कार्यक्रम के माध्यम से देश की विकास यात्रा को नई ताकत मिलेगी। इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों में ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला 'विकसित भारत संवाद' विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर, शून्य अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण जागरूकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों पर व्याख्यान, शहीद भगत सिंह जयंती के अवसर पर देशभक्ति कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यशालाएँ, निबंध, नुक्कड़ नाटक जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार, 'स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025' का क्रियान्वयन राज्य भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से किया जाएगा। इसमें जन स्वच्छता अभियान, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, स्वच्छ सुजल गाँव, स्वच्छ आरोग्यदायी स्ट्रीट फ़ूड जैसी विशेष गतिविधियाँ शामिल होंगी। गौरतलब है कि 25 सितंबर को देश भर के नागरिक 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ' के नारे के तहत श्रमदान अभियान में हाथ बँटाएँगे और स्वच्छता का संकल्प लेंगे। इसके अलावा, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (अइ) पर एक कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने युवाओं से इस व्याख्यानमाला को छात्रों के लिए एक प्रेरक मंच मानते हुए इसमें भाग लेने की अपील की।

मां के बाद पूजा खेडकर के पिता और बॉडीगार्ड भी लापता, ट्रक ड्राइवर के अपहरण मामले में हैं आरोपी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

ठाणे। पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर के पिता और उनके बॉडीगार्ड ट्रक ड्राइवर के अपहरण के मामले में फरार हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी उस एसयूवी गाड़ी के साथ रविवार से लापता हैं, जिसमें अपहरण किया गया था।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना शनिवार शाम नवी मुंबई के मुलुंड-ऐरोली रोड पर हुई। एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक पूजा खेडकर के परिवार की लैंड क्रूज़र कार से हल्का टकरा गया। इसके बाद कार में बैठे दो लोग, पूजा के पिता दिलीप खेडकर और उनके बॉडीगार्ड प्रफुल सालुंखे, ट्रक ड्राइवर प्रह्लाद कुमार से झगड़ पड़े। आरोप है कि उन्होंने कुमार को जबरन एसयूवी में बैठाया और उसे पुणे में मौजूद पूजा खेडकर के बंगले में ले गए। पुलिस ने रविवार को बंगले से ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया। नवी मुंबई के डीसीपी (जोन 1) पंकज दाहाने ने बताया कि अपहरण का मकसद एसयूवी को हुए नुकसान की भरपाई कराना था।

मां मनोरमा खेडकर भी हुई फरार

पूजा की मां मनोरमा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने रविवार को पुलिस को बंगले में घुसने से रोका। उन्होंने पुलिस को भरोसा दिलाया था कि दोपहर 3 बजे तक दोनों आरोपी पुलिस स्टेशन आ जाएंगे। लेकिन समय आने पर उन्होंने फोन पर पुलिस से साफ कहा, 'जो करना है कर लो।' जब पुलिस दोबारा बंगले पर पहुंची तो वहां न आरोपी थे, न ही वह एसयूवी। आरोप है कि मनोरमा ने ही गाड़ी हटवाई, आरोपियों को भगाया और बंगले के गेट पर दो खतरनाक कुत्ते छोड़ दिए, जिससे पुलिस अंदर नहीं जा पाई।

पूजा खेडकर के मां-पिता और बॉडीगार्ड की तलाश जारी

सोमवार को पुणे और नवी मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम ने फिर से बंगले की तलाशी ली। इस बार गेट बंद था, तो पुलिसकर्मी गेट फांदकर अंदर घुसे, लेकिन कोई नहीं मिला। नवी मुंबई पुलिस की शिकायत पर मनोहरमा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यह धारा सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़ी है। फिलहाल दिलीप खेडकर, उनके बॉडीगार्ड और मनोरमा खेडकर, तीनों की तलाश जारी है।

ऑस्ट्रेलियाई सांसदों ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विदेश मंत्री और सांसद टिम वाट्स ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सद्भावना भेंट की। इस अवसर पर, ऑस्ट्रेलिया और महाराष्ट्र के बीच कृषि, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, शिक्षा आदि क्षेत्रों में व्यावसायिक संबंधों को मज़बूत करने पर चर्चा हुई।

श्री वाट्स के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे से मुलाकात की। इस अवसर पर सांसद मिलिंद देवड़ा, उपमुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना आदि उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास में बहुमूल्य योगदान दे रहा है और हम बुनियादी ढाँचे के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में मेट्रो रेल, कोस्टल रोड, अटल सेतु जैसी विश्वस्तरीय परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नवी मुंबई में मेडिसिटी और एजुसिटी का निर्माण किया जा रहा है।

इस अवसर पर ऑस्ट्रेलियाई सांसद टिम वॉट्स का स्वागत करते हुए, उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे ने उन्हें मुंबई की पहचान माने जाने वाले वड़ा पाव की पेशकश की। श्री वॉट्स और वेस्टइंडीज़ में उनके ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्य दूत पॉल मर्फी ने विशेष रूप से इस भोजन का आनंद लिया। श्री वॉट्स ने याद किया कि बीस साल पहले वे एक क्रिकेट मैच देखने मुंबई आए थे।

केंद्र सरकार से प्याज निर्यात सब्सिडी दोगुनी करने की मांग- विपणन मंत्री जयकुमार रावल की जानकारी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार से प्याज निर्यात को प्रोत्साहित कर निर्यात सब्सिडी दोगुनी करने का अनुरोध किया है ताकि बाजार में प्याज की कीमतें बनी रहें और राज्य के प्याज उत्पादक किसानों को इसका लाभ मिल सके, विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने जानकारी दी।

प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के लिए विपणन मंत्री जयकुमार रावल की उपस्थिति में मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल, कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पाशा पटेल, विधायक श्री रमेश बोरनारे, विठ्ठल लांघे, विपणन विभाग के प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, विपणन महासंघ के प्रबंध निदेशक श्रीधर दुबे पाटिल, विपणन विभाग के संयुक्त सचिव विजय लहाणे सहित नेफेड और एनसीसीएफ के अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि सरकार राज्य के प्याज उत्पादक किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। यद्यपि प्याज का उत्पादन 55 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है, फिर भी वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्याज के निर्यात को प्रोत्साहित करना और अन्य उपाय करना आवश्यक है। इसके लिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार से प्याज निर्यात सब्सिडी को दोगुना करने की मांग की है। केंद्र सरकार की ओर से उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इससे विभिन्न देशों को प्याज निर्यात करके राज्य में प्याज की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी।

प्याज बाजार में समय-समय पर अफवाहें फैलाकर प्याज की कीमतें कम की जाती हैं। इससे कुछ व्यापारियों को फायदा होता है। इससे किसानों को भारी नुकसान होता है। इसके लिए, जिला कलेक्टर के नियंत्रण में सतर्कता समितियों को सक्रिय किया गया है और उन्हें अधिकार दिए गए हैं। इसलिए, प्याज की जमाखोरी और मुनाफाखोरी जैसी विभिन्न चीजों पर नजर रखी जाएगी, मंत्री श्री रावल ने बताया।

प्याज मूल्य वृद्धि उपायों के तहत, मंत्री श्री रावल ने महाराष्ट्र कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से राज्य की 28 कृषि उपज मंडी समितियों के अध्यक्षों और सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। मंडी समिति का मुख्य दायित्व किसानों द्वारा उत्पादित कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाना है। प्रत्येक मंडी समिति को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मंडी समिति को स्थानीय स्तर पर उन लोगों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने चाहिए जो किसानों को नुकसान पहुँचाने के इरादे से अधिक लाभ कमाने के लिए अफवाहें फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में कुशलतापूर्वक कार्य करने वाली कृषि उपज मंडी समितियों का मूल्यांकन किया जाएगा और सुदृढ़ीकरण योजना में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

आने वाले समय में, राज्य में किसान उत्पादक समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सौर ऊर्जा आधारित प्याज निर्जलीकरण परियोजना लागू की जाएगी और लगभग एक लाख मीट्रिक टन प्याज को निर्जलित करके उसका पाउडर और प्याज चिप्स बनाया जाएगा। साथ ही, इस उत्पाद का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विपणन भी किया जाएगा, ऐसा मंडी मंत्री जयकुमार रावल ने बताया।

ठाणे दोहरे हत्याकांड में मकोका के तहत सात गिरफ्तार; पुलिस का दावा- कई जघन्य अपराधों में शामिल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

ठाणे। पिछले महीने ठाणे जिले में दो चचेरे भाइयों की हत्या के मामले में गिरफ्तार सात आरोपियों के खिलाफ अब महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. डी.एस. स्वामी ने बताया कि इन सात आरोपियों में मुख्य साजिशकर्ता विक्की म्हात्रे भी शामिल है। ये सभी एक संगठित आपराधिक गिरोह का हिस्सा हैं, जो पिछले दस वर्षों से कई हिंसक अपराधों में शामिल रहा है।

पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह ने प्रफुल तांगड़ी (42 वर्षीय) को पुरानी रंजिश के चलते निशाना बनाया था। उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई और फिर 11 अगस्त को उनकी हत्या कर दी गई।

प्रफुल तांगड़ी पर हमला उनके भिवंडी के खर्डी गांव स्थित ऑफिस में किया गया। उन पर तलवारों और अन्य हथियारों से हमला किया गया। जब उनके चचेरे भाई और दफ्तर के कर्मचारी चेतन तांगड़ी (22 वर्षीय) उन्हें बचाने आए, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर उनकी हत्या कर दी।

भिवंडी तालुका पुलिस ने शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया। इसमें कई टीमें बनाई गईं और खुफिया जानकारी के साथ तकनीकी निगरानी का सहारा लेकर सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया।

पुलिस अधीक्षक ने बताया, जब हमने उनके आपराधिक इतिहास की जांच की, तो पाया कि ये लोग 2013 से गंभीर और जघन्य अपराधों में शामिल रहे हैं। इन अपराधों में अवैध जमावड़ा, मारपीट, हत्या की कोशिश और अवैध रूप से हथियार रखने जैसे मामले शामिल हैं। इनका लगातार अपराध करना यह दिखाता है कि यह एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे, इसलिए इन पर मकोका लगाना जरूरी हो गया। पुलिस अब इस गिरोह के नेटवर्क और इसके अन्य मामलों से संबंधों की जांच कर रही है।

अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस के अवसर पर 18 और 19 सितंबर को मुंबई में बांस सम्मेलन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। जलवायु परिवर्तन के संकट को रोककर मानव जाति को बचाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस के अवसर पर, महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान और फीनिक्स फाउंडेशन द्वारा मुंबई में दो दिवसीय बांस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन 18 और 19 सितंबर 2025 को मुंबई के यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागार में आयोजित किया जाएगा।

यह सम्मेलन 'लोगों, ग्रह और समृद्धि के लिए बांसः हरा सोना, हरित ऊर्जा, हरित पृथ्वी' की अवधारणा के साथ आयोजित किया गया है। यह दो दिवसीय सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगा। राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पर्यावरण सतत विकास कार्य बल के कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल ने इस सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए कहा।

आज पृथ्वी अभूतपूर्व पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल की आग, बादल फटने, बाढ़ और लू जैसी आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पाशा पटेल ने कहा कि बांस एक 'कल्पवृक्ष' है और कार्बन अवशोषण, वनों की कटाई को रोकने और जैव ईंधन के उत्पादन में उपयोगी है।

इस सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान (मित्रा) और फीनिक्स फाउंडेशन, लोदगा, जिला लातूर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बांस सम्मेलन महाराष्ट्र को बांस की राजधानी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्री पटेल ने कहा कि मुंबई के यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में देश और राज्य भर से विशेषज्ञों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों, किसानों और नीति निर्माताओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें मानव जाति के अस्तित्व पर महत्वपूर्ण चर्चाएँ होंगी। इसमें बांस से लेकर इथेनॉल, मेथेनॉल, थर्मल के लिए बांस के फूस, लोहा, कोयला, लकड़ी, फर्नीचर, बांस के कपड़े, कौशल, पर्यावरण, प्लास्टिक मुक्ति जैसे कई उद्योगों के सतत विकास की ओर बढ़ने की उम्मीद है। शहरी वन, ऑक्सीजन पार्क, ग्रीन बिल्डिंग जैसे कई नवाचार इस सम्मेलन से सामने आएंगे।

'फैसले के खिलाफ हर कोई अपील नहीं कर सकता', मालेगांव मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी

मुंबई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ किया है कि किसी आरोपी की बरी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। अदालत ने कहा कि यह कोई खुला दरवाजा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपील लेकर पहुंच जाए। हाईकोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि मृतकों के परिजनों को ट्रायल के दौरान गवाह बनाया गया था या नहीं।

यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकड़ की खंडपीठ ने की। अदालत छह पीड़ितों के परिजनों द्वारा दायर अपील सुन रही थी, जिसमें विशेष एनआईए अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें सात आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इन आरोपियों में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल थे।

परिजनों के गवाह बनने पर सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या पीड़ित परिवारों के सदस्य गवाह थे। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि पहले अपीलकर्ता निसार अहमद, जिनके बेटे की मौत धमाके में हुई थी, ट्रायल में गवाह नहीं बने थे। इस पर अदालत ने कहा कि अगर बेटे की मौत हुई थी तो पिता को गवाह होना चाहिए था। अदालत ने आदेश दिया कि इस बारे में पूरी जानकारी बुधवार को दी जाए।

अपीलकर्ताओं का तर्क

परिजनों की ओर से दाखिल अपील में कहा गया है कि जांच में खामियां होना या जांच एजेंसियों की गलती होना बरी करने का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि ब्लास्ट की साजिश गुप्त तरीके से रची गई थी, इसलिए उसका सीधा सबूत मिलना संभव नहीं था। अपील में यह भी कहा गया कि 31 जुलाई को एनआईए की विशेष अदालत द्वारा दिया गया फैसला गलत और कानून के खिलाफ था, जिसे रद्द किया जाना चाहिए।

2008 का धमाका और नुकसान

29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव कस्बे में एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिल में बंधा विस्फोटक धमाका कर गया था। इस धमाके में छह लोगों की मौत हुई और 101 लोग घायल हुए थे। घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया था। उस समय एटीएस ने मामले की जांच कर सात लोगों को गिरफ्तार किया था और एक बड़े आतंकी साजिश का खुलासा किया था। अपील में आरोप लगाया गया है कि जब एनआईए ने मामले को अपने हाथ में लिया तो उसने आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप कमजोर कर दिए। अपीलकर्ताओं ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केवल पोस्ट ऑफिस की तरह काम किया और अभियोजन की कमियों का फायदा आरोपियों को मिल गया।

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे

'भाजपा का ढोंग उजागर हो गया'

मुंबई। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने से भाजपा की देशभक्ति का ढोंग उजागर हो गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश को इसमें भाग न लेकर दृढ़ता दिखानी चाहिए थी। भारत ने रविवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से हरा दिया। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के चलते सोशल मीडिया पर इस मैच का बहिष्कार करने की मांग उठ रही थी। पाकिस्तान से मैच खेलने को लेकर बीसीसीआई की भी आलोचना हो रही है।

ठाकरे बोले- पाकिस्तान के साथ न खेलकर दृढ़ता दिखानी चाहिए थी

ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'भाजपा का ढोंग उजागर हो गया है। भारत को (पाकिस्तान के साथ

क्रिकेट मैच) न खेलकर दृढ़ता दिखानी चाहिए थी।' ठाकरे ने कहा कि अब यह साफ है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कई देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के बावजूद भारत को देशों से समर्थन क्यों नहीं मिला। ठाकरे ने कहा, 'जब हमने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है, तो दुनिया आपसे सवाल पूछेगी। आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं या दोस्त? अगर आप उनके दुश्मन हैं, तो सारे रिश्ते तोड़ दीजिए।'

राज्य पर बढ़ते कर्ज पर जताई चिंता

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्रिकेट मैच विवाद में भाजपा का समर्थन करने के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, 'उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, देश नहीं।' ठाकरे ने महायुति सरकार पर 9 लाख करोड़ रुपये के बढ़ते कर्ज और खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद नई योजनाएं शुरू करने पर भी निशाना साधा। राज्य पर बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, 'अगर आप ठेकेदारों के फायदे के लिए कर्ज ले रहे हैं और बांध, पुल और सड़कें बनवा रहे हैं, तो मैं इसे विकास नहीं कहूंगा। कर्ज कम करने पर ध्यान देना जरूरी है।'

सम्पादकीय

मणिपुर में विकास और शांति की एक नई भोर

मई 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद मैतेयी और कुकी समुदायों के मध्य भड़की हिंसा से अब तक 260 लोग मारे जा चुके हैं तथा 60 हजार से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस संघर्ष के आरम्भ से ही भारत के सभी विपक्षी दल निरंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सरकार पर हमलावर थे, उनका एक ही प्रश्न था कि मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे ? मणिपुर को लेकर संसद ठप रखी गई। मणिपुर में महिलाओं पर हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की खंडपीठ ने मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां का दौरा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी व अन्य नेतागण अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए मणिपुर के हालातों को हथियार बनाते रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कई अवसरों पर मणिपुर पर अपनी चिंता व्यक्त की। विरोधी दलों के भारी दबाव के कारण भाजपा को अपनी ही सरकार हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मणिपुर दौरे से सभी को उचित उत्तर दे दिया है किंतु अब विरोधी दलों को इसमें रुचि नहीं रही क्योंकि उनका मणिपुर नैरेटिव फिलहाल समाप्त होता दिख रहा है। जिस समय भारत में मणिपुर हिंसा पर राजनीति चरम पर थी उस समय यूरोपीय संघ की संसद में मणिपुर को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसे केंद्र सरकार ने भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बताते हुए खारिज कर दिया था अतः मणिपुर को लेकर कांग्रेस ने जो देश विरोधी वैश्विक नैरेटिव चलाया था वह भी अब ध्वस्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुकी बहुल हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित चुराचांदपुर के लिए 7, 300 करोड़ रुपए से अधिक और मैतेई बहुल इंफाल के लिए 1, 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा करके यह संदेश देने का प्रयास किया कि सरकार ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत उनके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर यात्रा के दौरान हिंसा पीड़ितों से भेंट करते हुए उन्हें सुरक्षा शांति तथा विकास का भरोसा दिया।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मणिपुर को भारत की मणि बताते हुए कहा कि मणिपुर में उम्मीद और विश्वास की नई सुबह दस्तक दे रही है। किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति बहुत अनिवार्य है। आपसी संवाद और भरोसे से ही विवाद को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार मणिपुर के विभिन्न समुदायों के बीच आपसी संवाद, सम्मान और समझौते को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास रही है।

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पूर्व गृह मंत्रालय के लगातार प्रयासों के बाद दोनो समुदायों के बीच तनाव कम करने के काफी प्रयास किये है जिनका प्रभाव दिखाई पड़ने लगा है। लगातार चल रहे संवाद के कारण ही कुकी बहुल क्षेत्र से होकर निकलने वाला एनएच दो हाईवे अब पूरी तरह से खुल गया है और जनता व वस्तुओं की आवाजाही शुरू हो चुकी है। मणिपुर में अभी शांति के लिए कई अहम पड़ाव आने हैं। मैतेयी ओर कुकी समुदाय के बीच कुछ मतभेद अभी भी बरकरार हैं जिनको सुलझाने के प्रयास जारी हैं। इसमें कुकी समुदाय के लोग मणिपुर की छत के नीचे ही अपने लिए एक अलग व्यवस्था की मांग कर रहे हैं फिर भी अब मणिपुर की समस्या का उचित समाधान निकलने की आस जग गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद एक रैली को संबोधित किया जिसमें लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी जो मोदी-मोदी के नारे लगा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जनसमुदाय मान चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से मणिपुर में विकास और शांति लाने वाली एक नयी भोर हुई है।

प्रधानमंत्री का संवाद देश और दिलों को जोड़ता है

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपना 75 वां जन्मदिन बुधवार को मनाएंगे। उनकी जीवन यात्रा रचना, सृजन और संघर्ष की त्रिवेणी है। उनके व्यक्तित्व का सबसे खास पक्ष है संचार और संवाद।

भारत जैसे महादेश को संबोधित करना आसान नहीं है। इस विविधता भरे देश में वाक् चातुर्य से भरे विद्वानों, राजनेताओं, प्रवचनकारों और अदीबों की कमी नहीं है। अपनी वाणी से सम्मोहित कर लेने वाले अनेक विद्वानों को हमने सुना और परखा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमताएं उनमें विलक्षण हैं। वे हमारे समय के अप्रतिम संचारकर्ता हैं। संचार का विद्यार्थी होने के नाते मैं उनकी तरफ बहुत विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखता हूं, किंतु वे अपनी देहभाषा, भाव-भंगिमा, शब्दावली और वाक् चातुर्य से जो करते हैं, उसमें कमियां ढूंढ पाना मुश्किल है। उनका आत्मविश्वास और शैली तो विलक्षण है ही, वे जो कहते हैं उस बात पर भी सहज विश्वास करने का मन होता है। मोदी सही मायने में संवाद के महारथी हैं। वे जनसभाओं के नायक हैं तो एक्स जैसे नए माध्यमों पर भी उनकी तूती बोलती है। पारंपरिक मंचों से लेकर आधुनिक सोशल मीडिया मंचों पर उनकी धमाकेदार उपस्थिति बताती है संवाद और संचार को वे किस बेहतर अंदाज में समझते हैं।

गुजरात के एक छोटे से कस्बे बड़नगर में पले-बढ़े नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो लोगों को सम्मोहित करता है? उनकी राजनीतिक यात्रा भी विवादों से परे नहीं रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें जिस तरह निशाना बनाकर उनकी छवि मलिन करने के सचेतन प्रयास हुए, वे सारे प्रसंग लोकविमर्श में हैं। बावजूद इसके वे हिंदुस्तानी समाज के नायक बने

हुए हैं तो इसके पीछे उनकी संप्रेषण कला और देहभाषा का अध्ययन प्रासंगिक हो जाता है। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो कभी सांसद नहीं थे और पहली बार लोकसभा पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 के आमचुनावों की याद करें तो देश किस तरह निराशा और अवसाद से भरा हुआ था। लोग राजनीति और राजनेताओं से उम्मादें छोड़ चुके थे। अन्ना आंदोलन से एक अलग तरह का गुस्सा लोगों के मन में पनप रहा था। तभी एक आवाज गूंजती है 'मैं देश नहीं झुकने दूंगा।' दूसरी आवाज थी 'अच्छे दिन आने वाले हैं।' ये दो आवाजें थीं नरेंद्र मोदी की, जो देश को एक विकल्प देने के लिए मैदान में थे। राजनीति में आश्वासनपरक आवाजों का बहुत मतलब नहीं होता, क्योंकि राजनीति तो सपनों और आश्वासनों के आधार पर ही की जाती है। किंतु नरेंद्र मोदी ने इस दौर में जो कुछ कहा उसे देश ने बहुत ध्यान से सुना। उनका दल लंबे समय से सत्ता से बाहर था और वे अपने दल की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए जा चुके थे। जाहिर है अवसाद और निराशा से भरी जनता को एक अवसर था परख करने का। मोदी इस अवसर का लाभ उठाते हैं और जनता के मन में भरोसा जगाने का प्रयास करते हैं। वे लगातार अपनी सभाओं में कहते हैं कि वे ही इस देश को उसके संकटों से उबार सकने की क्षमता से लैस हैं। जनता मुग्ध होकर उनके भाषणों को सुनती है। अपनी अप्रतिम संवादकला से वे लोगों में यह भरोसा जगाने में सफल हो जाते हैं कि वे कुछ कर सकते हैं।

2014 में मोदी सत्ता में आते हैं और संचार के सबसे प्रभावकारी माध्यम को साधते हैं। वे आकाशवाणी पर 'मन की बात' के माध्यम से लोगों से संवाद का अवसर चुनते हैं। यानि उनका संवाद अवसर और चुनाव केंद्रित नहीं है, निरंतर है। उनमें एक सातत्य है। बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, लोकजागरण के लिए। वे मन की बात को राजनीतिक विमर्शों के बजाए लोकविमर्शों का केंद्र बनाते हैं। जिसमें जिंदगी की बात है, सफाई की बात है, शिक्षा और परीक्षा की बात है, योग की बात है। मन की बात के माध्यम से वे खुद को एक ऐसे अभिभावक की तरह पेश करने में सफल होते हैं, जिसे देश और देशवासियों की चिंता है। संवाद की यही सफलता है और यही उसका उद्देश्य है। अपने लक्ष्य समूह को निरंतर अपने साथ जोड़े रखना मोदी की संवाद कला की दूसरी सफलता है। करोना संकट में भी हमने देखा कि उनकी अपीलों को किस तरह जनमानस ने स्वीकार किया, चाहे वे करोना वारियर्स के सम्मान में दीप जलाने और थाली बजाने की ही क्यों न हों। यह बातें बताती हैं कि अपने नायक पर देश का भरोसा किस तरह कायम है।

मोदी अपनी देहभाषा से कमाल करते हैं। कई बार चौंकाते भी हैं। देश की गहरी समझ भी इसका बड़ा कारण है, यही कारण है वे देश के जिस हिस्से में होते हैं वहां की स्थानीय बोली, वस्त्रों और प्रतीकों का सचेत इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही उनकी पोशाकें, उनका हाफ कुर्ता, जैकेट्स आज एक तरह से स्टाइल स्टेटमेंट है। उनका अनुसरण कर नौजवान आज खद्दर और सूती कपड़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हम विश्लेषण करें तो पाते हैं कि उनका समर्पित जीवन और ईमानदारी से उनकी वाणी का भी एक रिश्ता है। जब हम सिर्फ बोलते हैं तो उसका असर अलग होता है। किंतु अगर हम जो बोलते हैं उसमें कृतित्व भी शामिल हो तो बात का असर बढ़ जाता है। नरेंद्र मोदी अपनी असंदिग्ध ईमानदारी, राष्ट्रनिष्ठा और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनका समूचा जीवन राष्ट्र के लिए अर्पित है। ऐसा व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आपकी वाणी को आपके जीवन का समर्थन है। सिर्फ देश की बात करना और देश के लिए जीना दो बातें हैं। मुझे लगता है जीवन और कर्म में एक रूप होने के नाते मोदी बाकी राजनेताओं से बहुत आगे निकल जाते हैं। क्योंकि उनकी राष्ट्रनिष्ठा पर सबको भरोसा है, इसलिए उनकी वाणी पर भी सहज विश्वास आता है। इस तरह उनकी वाणी 'भाषण' न होकर 'हृदय से हृदय के संवाद' में बदल जाती है। लोगों को भरोसा है कि वे हमारी ही बात कर रहे हैं और हमारे लिए ही कर रहे हैं। मोदी ने अपनी साधारण पृष्ठभूमि की बात कभी छिपाई नहीं, जब भी उनकी साधारण स्थितियों का मजाक बनाया गया तो उसे भी उन्होंने एक सफल अभियान में बदल दिया। 'चाय पर चर्चा' का कार्यक्रम किस तरह बना, उसके संदर्भ हम सबके ध्यान में हैं। नरेंद्र मोदी सही मायने में सामान्य जनों में भरोसा जगाते हैं कि अगर संकल्प हों, इच्छाशक्ति हो तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। यह एक बात लोगों को उनसे कनेक्ट करती है। अनेक राजनेता हैं, जो साधारण पृष्ठभूमि से आए हैं। किंतु उनका या तो अपनी जड़ों से उनका रिश्ता टूट गया है या वे उन विधिकाओं को याद नहीं करना चाहते। जबकि नरेंद्र मोदी अपनी जड़ों को नहीं भूलते वे हमेशा उसे याद करते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं। यही कारण है उनका कनेक्ट सीधा जनता से बनता है। वे प्रधानमंत्री होकर भी अपने से नजर आते हैं। संचार, संवाद और पोजिशिनिंग की यह कला उनमें सहज है। बिना जतन के भी वे इन सबको साधते हैं और साधते रहेंगें क्योंकि आसमान पर होकर भी माटी की सोंधी महक उन्हें जड़ों से जोड़े रखती है। इसलिए उनका संवाद दिलों को जोड़ता है, देश को भी।

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में हुए सुप्रीम संशोधन के मायने

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन उसके कुछेक प्रावधानों में विधिसम्मत और तर्कसंगत संशोधन किया है या फिर पूरी तरह से उन पर रोक लगा दी है। इसलिए वक्फ संशोधन अधिनियम में हुए सुप्रीम संशोधन के मायने समझना बहुत जरूरी है। लोगों को उम्मीद है कि कोर्ट के इस ताजातरीन फैसले से वे आशंकाएं दूर हो जाएंगी, जो इस नए कानून को लेकर इससे पहले जताई जा रही थीं। चूंकि कोर्ट का यह निर्णय संविधान के अनुरूप है, इसलिए दोनों पक्षों ने इसे मान लिया है। यह एक शुभ लक्षण है।

बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए संशोधन महत्वपूर्ण और जरूरी हैं, क्योंकि इनमें संविधान की भावनाओं का भी ख्याल रखा गया है। इसलिए इसके परिवर्तित मायने राष्ट्रीय एकता के लिहाज से अहम हैं।

पहला, कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था, बताया गया है। हालांकि यह रोक तभी तक लागू रहेगा जब तक राज्य सरकारें इसके लिए अलग से नियम नहीं बना देतीं। चूंकि यह शर्त मनमानी हो सकती थी, इसलिए अदालत ने इसे स्थगित कर दिया है। समझा जाता है कि वक्फ करने के लिए न्यूनतम 5 बरसों तक इस्लाम का अनुयायी होने के प्रावधान पर तब तक रोक रहेगी, जब तक राज्य सरकारें इसके सत्यापन के लिए नियम नहीं बना लेती। चूंकि देश में धर्म व्यक्तिगत मामला है और यह जरूरी नहीं कि कोई नागरिक अपनी धार्मिक पहचान का सार्वजनिक प्रदर्शन करे। इसलिए यह तय करना कि कोई किसी धर्म को कब से मान रहा है, बेहद जटिल है। राज्य सरकारों से उम्मीद है कि इस बारे में नियम बनाते समय वे सभी पहलुओं का ध्यान रखेंगी और ज्यादा संवेदनशीलता बरतेंगी।

दूसरा, कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया है कि जिला कलेक्टर को यह फैसला देने का अधिकार नहीं है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल या कोर्ट अंतिम निर्णय न कर ले। इससे कलेक्टर की शक्ति सीमित हुई है और मनमानी पर रोक लगी है। यह एक अहम संशोधन है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने वक्फ संपत्ति जांच के प्रावधानों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नामित अधिकारी की आंशिक रूप से रिपोर्ट के आधार पर ही किसी प्रॉपर्टी को गैर-वक्फ नहीं माना जा सकता। समझा जाता है कि अदालत ने संपत्ति अधिकार तय करने की ताकत जिलाधिकारी को देने को संविधान में की गई व्यवस्था शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ माना है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है, ताकि लोकतंत्र के तीनों अहम अंगों- विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का संतुलन बना रहे। एक पक्ष की ओर पलड़े का थोड़ा भी झुकाव व्यवस्था के संतुलन को

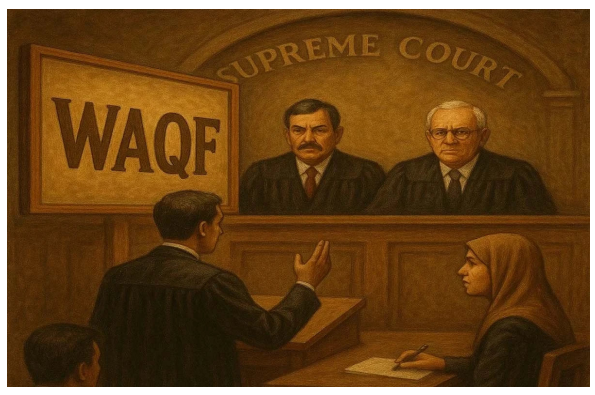

बिगाड़ देगा।

तीसरा, वक्फ बोर्ड में सदस्यों की संख्या और गैर-मुस्लिम सदस्यों की सीमा में संशोधन भी कुछ हद तक सुरक्षित की गई है, लेकिन कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर स्थगन लगाया है। लिहाजा लोगों को उम्मीद है कि अब उनकी सरकार अन्य धर्मों के लिए भी इसी तरह के कानून लाएगी व उसका अनुपालन का निर्णय करेगी।

चतुर्थ, कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को शक्ति के 'मनमाने' प्रयोग को रोकने के लिए अस्थायी रूप से स्थगित किया है, जिसमें वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और बुजुर्गों का धर्म पालन जैसे मुद्दे शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के कई बिंदुओं पर विपक्ष को गहरी आपत्ति थी। इसे लेकर दोनों सदनों में और सड़क पर भी काफी हंगामा हुआ। इस मामले की गंभीरता और उसके असर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिम्मेदारी भरा है।

यूँ तो इस बाबत दायर याचिका में पूरे कानून को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे नहीं माना। इस तरह के कदम बेहद दुर्लभ मामलों में उठाए जाते है और इनका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। देखा जाए तो इस मायने में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया, और यह भी ध्यान रखा कि विधायिका के साथ सीमाओं का अतिक्रमण न हो। इसलिए उसने समझदारी पूर्वक बीच का रास्ता निकाला है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले में बेहद संतुलित नज़रिया अपनाया है।

सच कहा जाए तो कोर्ट का यह फैसला वक्फ कानून में संतुलित नज़रिया को अधिक न्यायसंगत और संवैधानिक बनाने की दिशा में संकेत देता है। साथ ही इसके मार्फ़त सरकारी शक्तियों और व्यक्तिगत अधिकारों का संतुलन बनाने का प्रयास भी किया गया है। कोर्ट के इस फैसले से संबंधित कुछ नियम और प्रावधान तभी तक लागू नहीं होंगे, जब तक इस बारे में अधिक स्पष्ट नियम और निर्देश नहीं बन जाते।

इस तरह से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जबकि पूरे कानून पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है। ऐसा करके उसने एक ओर जहां संतुलित नजरिया अपनाते हुए शक्ति का संतुलन बिठाने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर वक्फ कानून पर फैसला देते हुए उसने अतिरिक्त संवेदनशीलता की जरूरत भी समझी है। यही वजह है कि अपेक्षाकृत विवादास्पद मामलों में उसका एक और जिम्मेदारी भरा निर्णय सामने आया है, जिससे देश-प्रदेश ने राहत की सांस ली है।

नेपाल के जेन-जेड के साथ फिर बड़ा धोखा हो गया क्या?

नेपाल और नेपाल जैसे कई लोकतांत्रिक देशों में युवाओं के साथ लगातार छल होता रहा है। कई देशों में युवाओं ने सड़क पर उतर कर अपने साथ किए गए धोखे का जवाब भी देने की कोशिश की लेकिन विडंबना देखिए कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी युवाओं के हाथ अंत में खाली ही रह जाते हैं। नेपाल के ज्यादातर युवा आंदोलनकारी अपने आपको अब इसी स्थिति में महसूस कर रहे हैं।

हिंसा या हिंसक आंदोलन को किसी भी स्थिति में जायज नहीं ठहराया जा सकता। यह भी अपने आप में एक तथ्य है कि नेपाल में जिस तेजी से अचानक जेन-जेड युवा आक्रमक अंदाज में सड़कों पर उतर गए, उसमें किसी विदेशी ताकत के हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी यह स्थापित तथ्य है कि दुनिया का कोई भी देश किसी भी देश में गड़बड़ी तभी करा पाता है,जब उस देश में लोगों का असंतोष चरम पर पहुंच जाता है। नेपाल में उसी तरह के हालात बन गए थे,इससे भला कौन इनकार कर सकता है।

नेपाल की सड़कों पर उतर कर हंगामा करने वाले जेन-जेड प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, राजनीतिक अव्यवस्था एवं भाई-भतीजावाद को खत्म करने के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगे प्रतिबंध को हटाना था। लेकिन सड़कों पर उतरे युवा एक सुर में कह रहे थे कि उन्होंने अपने देश में बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर आंदोलन किया है।

नेपाली युवा एक सुर में सत्ता सुख भोग रहे या सत्ता सुख भोग चुके नेताओं को पूरी तरह से हटा देना चाहते थे। लेकिन क्या वाकई उनकी यह मंशा पूरी हुई ? नेपाल में शांति स्थापित करने के नाम पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता सौंप दी गई है।

आपको बता दें कि, 7 जून 1952 को जन्मी सुशीला कार्की, नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही, वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। लेकिन बुजुर्ग नेताओं से त्रस्त नेपाल को शांति स्थापित करने के नाम पर 73 वर्ष की एक नई प्रधानमंत्री के हाथों में सौंप दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि क्या 73 वर्ष की सुशीला कार्की नेपाल के जेन-जेड प्रदर्शनकारियों के साथ न्याय कर पाएंगी? उनकी परेशानियों और दिक्कतों को समझ कर, दूर कर पाएंगी ? अगर सिर्फ चुनाव करा देना ही समस्या का समाधान होता तो नेपाली युवाओं को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता? यह भी ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति (भले ही वह किसी भी पद पर रहा हो) सत्ता प्रतिष्ठान का हिस्सा रहा हो वो उस व्यवस्था में कभी भी बड़ा और व्यापक बदलाव नहीं ला सकता है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने बड़े बवाल के बावजूद बुजुर्ग नेताओं के रवैए में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ये सब आज भी अपने-अपने राजनीतिक दलों पर कब्जा जमाए बैठे हैं और अभी से इन्होंने बदलाव का विरोध करना शुरू कर दिया है।

नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने शुक्रवार शाम को सुशीला कार्की को शीतल निवास में अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति पौडेल ने संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 2015 में नए संविधान के लागू होने के बाद से सभी पिछली सरकारें अनुच्छेद 76 के तहत गठित हुई थीं लेकिन पहली बार अनुच्छेद 61 के तहत कार्की को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से यह भी बताया गया है कि अंतरिम प्रधानमंत्री को छह महीने के भीतर देश में चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। गौर कीजिएगा, सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण समारोह का नेपाल की संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों और सांसदों ने बहिष्कार किया। राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिलने पर भी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर देवराज घिमिरे और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहल शपथ ग्रहण समरोह में नहीं पहुंचे। ध्यान रहे, घिमिरे केपी ओली की पार्टी के सांसद हैं जबकि दहल पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचण्ड की पार्टी के नेता है। नेपाल के राजनीतिक दल या दूसरे शब्दों में कहें तो नेपाल के बुजुर्ग नेता संसद भंग के फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अगर 6 महीने के भीतर जब भी चुनाव होंगे तो यही राजनीतिक दल और यही नेता तो लड़ेंगे। चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो यही बुजुर्ग नेता आपस में जोड़-तोड़ कर सरकार बनाएंगे और मिल कर नेपाल की जनता खासकर नेपाली जेन-जेड के सपनों को रौंदते रहेंगे। नेपाल के जेन-जेड ने नेताओं की संगठित लूट को फिर से देखने के लिए तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं ही किया था।

नेपाल से सीखा सबक! भारत में आंदोलनों का अध्ययन कर भविष्य की रणनीति बनाएगी मोदी सरकार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में यह निर्देश दिया है कि 1974 से अब तक देश में हुए प्रमुख आंदोलनों का गहन अध्ययन किया जाए, ताकि यह समझा जा सके कि किन कारणों से बड़े पैमाने पर असंतोष पनपता है और भविष्य में 'स्वार्थी तत्वों' द्वारा आंदोलन की आड़ में अशांति फैलाने की संभावनाओं को रोका जा सके।

देखा जाये तो 1974 का वर्ष भारतीय राजनीति में विशेष महत्व रखता है। यह वही दौर था जब जेपी आंदोलन ने बिहार से उठकर राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण किया और अंततः 1975 में आपातकाल की पृष्ठभूमि बनी। उसके बाद से छात्र आंदोलनों, किसान आंदोलनों, आरक्षण विरोधी और समर्थनकारी आंदोलनों, अन्ना हज़ारे का भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन, शाहीन बाग का नागरिकता संशोधन कानून विरोध और हालिया किसान आंदोलन, ये सभी भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के निर्णायक पड़ाव रहे हैं।

देखा जाये तो अमित शाह का यह कदम मात्र अतीत की घटनाओं की सूची तैयार करना नहीं है, बल्कि आंदोलन की प्रकृति, उनकी पृष्ठभूमि, उनसे हुई सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल और उनके सकारात्मक या नकारात्मक परिणामों को समझना है। सवाल यह है कि कौन-से आंदोलन वास्तविक जनआकांक्षाओं के प्रतिनिधि थे? किन आंदोलनों को संगठित समूहों या बाहरी ताकतों ने दिशा दी? आंदोलन कब लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा बने और कब हिंसा या अराजकता में बदल गए? इन सवालों का उत्तर ढूंढ़ना इस अध्ययन का मूल मकसद प्रतीत होता है।

मोदी सरकार की इस कवायद के वर्तमान संदर्भ में मायने समझें तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि आज भारत ऐसे समय में है जब सूचना और संचार तकनीक ने आंदोलन करने की शैली को बदल दिया है। सोशल मीडिया के ज़रिए आंदोलन बहुत तेज़ी से आकार ले सकते हैं। साथ ही स्थानीय असंतोष देखते-देखते राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। इसके अलावा, विपक्षी दल और अंतरराष्ट्रीय मंच भी आंदोलनों को राजनीतिक रंग देने में सक्रिय रहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्रालय की इस पहल के कई मायने हैं। जैसे- सरकार आंदोलन के पीछे छिपी वास्तविक सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को समझकर बेहतर नीतियाँ बना सकेगी। साथ ही अगर किसी आंदोलन को विदेशी या विध्वंसकारी ताकतें भड़काती हैं, तो उनकी पहचान करना आसान होगा। इसके अलावा, मोदी सरकार यह भी दर्शाना चाहती है कि वह लोकतांत्रिक अधिकारों और अनुशासन के बीच संतुलन कायम रखने के पक्ष में है। मोदी सरकार का यह निर्णय यह भी बताता है कि केंद्र सरकार आंदोलनों की राजनीति को सिर्फ तात्कालिक चुनौती नहीं मानती, बल्कि दीर्घकालिक नीति-चिंतन के विषय के रूप में देख रही है।

हालाँकि, सरकार के इस फैसले की आलोचनाएँ होनी भी संभव हैं। विपक्ष इसे 'आंदोलनों को बदनाम करने की कोशिश' कह सकता है। देखा जाये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन असहमति जताने का वैध साधन हैं, ऐसे में उनका अध्ययन करने को कुछ लोग नागरिक अधिकारों पर अंकुश की तैयारी मान सकते हैं। वैसे अमित शाह का यह निर्णय केवल अतीत को खंगालने का नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति को दिशा देने का प्रयास है। यह कदम यह स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार आंदोलन की राजनीति को हल्के में नहीं ले रही और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता से जोड़कर देख रही है। अब देखना होगा कि यह अध्ययन संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है या फिर केवल आंदोलनों को 'स्वार्थी तत्वों' की कारस्तानी करार देने तक सीमित रह जाता है।

हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि नेपाल में जेन-ज़ेड युवाओं के आंदोलन ने यह दिखाया है कि नई पीढ़ी पारंपरिक राजनीति से असंतोष प्रकट करने के लिए सड़कों पर उतरने से हिचकती नहीं। इसके अलावा, दक्षिण एशिया के अन्य देशों– जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हाल में जन आंदोलनों ने सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक उथल-पुथल को जन्म दिया है। दुनिया के अन्य हिस्सों में अरब स्प्रिंग के उदाहरण से यह स्पष्ट हो चुका है कि जनता की असंतुष्टि, यदि समय रहते संभाली नहीं जाए, तो वह तख़्तापलट या शासन परिवर्तन का कारण बन सकती है।

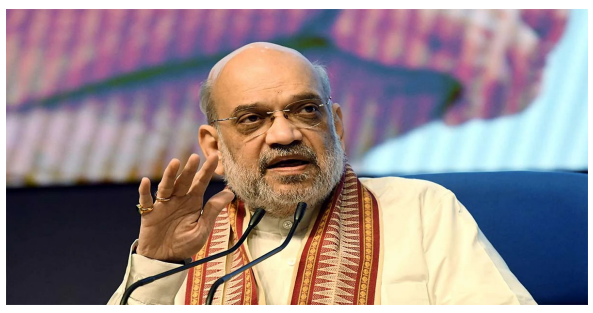

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दशहरा एवं दुर्गा पूजा की तैयारियों के सम्बंध में बैठक सम्पन्न

पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई, पेड़ो की छटाई, स्ट्रीट लाइटों एवं सड़कों की मरम्मत सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को संगम सभागार में दशहरा एवं दुर्गापूजा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन, कार्यदायी विभागों के अधिकारियों व दुर्गापूजा एवं रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी सम्बंधित अधिकारी अपने-अपने विभागों से सम्बंधित कार्यों को समय से पूर्ण कर लें। उन्होंने समितियों के पदाधिकारियों से आयोजन को सकुशल सम्पन्न कराने में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत, नालियों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग की व्यवस्था सहित आदि व्यवस्थायें समय से कराये जाने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए है। उन्होंने दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु बनाये गये तालाबों की साफ-सफाई कराने के साथ ही स्वच्छ पानी भरवाने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग एवं नगर निगम के अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कराने के साथ ही लटके जर्जर तारों की मरम्मत, खराब

ट्रांसफार्मरों को बदलने, रास्तों पर लटकते पेढ़ों की टहनियों की छटाई कराने तथा नगर निगम को स्ट्रीट लाइटो को सही कराने का निर्देश दिया है। जिलाधिकरी ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को संयुक्त रूप से भ्रमण करके सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराये जाने एवं संवेदनशील स्थानों का भी अवश्य भ्रमण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एम्बुलेंस एवं डॉक्टरों की टीम की उपलब्धता कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने नगर निगम को छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है।

उन्होंने सभी सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को भ्रमण कर मेला मार्गों की कमियों को दूर कराये जाने के लिए कहा है। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज विभाग को साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी गैर परम्परागत कार्य नहीं होगा। फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। यातायात की व्यवस्था, डायवर्जन तथा पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित रहे। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित रहे। अपराध निरोधक, सिविल डिफेंस तथा अन्य सहयोगी विभाग के लोगो की शिफ्ट वाइस ड्यूटी लगायी जाये।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्रीमती पूजा मिश्रा, अपर जिलाधिकारी नगर सत्यम मिश्र, अपर नगर आयुक्त, उपजिलाधिकारीगण, एसीपीगण सहित रामलीला एवं दुर्गापूजा कमेटी के पदाधिकारीगणों सहित सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस उपायुक्त गंगानगर द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई कर फरियादियों की शिकायतें सुनी गई तथा निस्तारण हेतु सम्बंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

हिन्दी दिवस पखवाड़ा के अन्तर्गत निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। राजभाषा हिन्दी पखवाड़ा के अन्तर्गत बुलंदी साहित्यिक सेवा समिति अन्तर्राष्ट्रीय उत्तराखंड द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजौना जसरा-प्रयागराज में संस्था द्वारा हिन्दी भाषा पर आधारित चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्राथमिक व जूनियर स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले दीक्षा यादव, दीपिका विश्वकर्मा, आदर्श पाल, सोनम यादव, प्रीति पाल, सुशांत, रागिनी यादव, सोनाक्षी यादव, आकाश पटेल, रिशू यादव, चंचल पटेल, प्रियांशी शर्मा स्वरा केसरवानी, लाडो यादव, अंशू पटेल अंशिका पटेल, प्रतीक्षा को प्रशस्ति पत्र, मेडल व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।यह प्रतियोगिता संस्था के अध्यक्ष विवेक बादल बाजपुरी, संरक्षक पंकज शर्मा, महामंत्री भारतेन्द्र त्रिपाठी के दिशा निर्देशन में और विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्यामाकांत द्विवेदी के संयोजन में आयोजित की गई। प्रधानाध्यापक श्यामाकांत द्विवेदी ने कहा कि हमारी मातृभाषा हमारा अभिमान है हम सबको उस पर नाज़ होना चाहिए।बुलंदी साहित्यिक संस्था द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सराहनीय योगदान है।इस अवसर पर विद्यालय के भारतेन्द्र त्रिपाठी, सुनील कुमार शुक्ल, इरफ़ान अहमद, नाज़िया सुल्ताना, जितेन्द्र कुमार शर्मा , शिशिर जायसवाल, आशीष कुमार गुप्ता, शरद कुमार, राकेश कुमार, पूनम तिवारी पंकज कुमार गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने 'स्वच्छता ही सेवा' की दिलाई शपथ

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित लोगों को 'स्वच्छता ही सेवा' की शपथ दिलाई स्वच्छता ही सेवा-2025 के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को संगम सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों को 'स्वच्छता ही सेवा' की शपथ दिलाई और सभी से स्वच्छता पखवाड़ा में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने श्रमदान के माध्यम से घर और सार्वजनिक स्थानों की सफाई कर अन्य लोगों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रेरित करने को कहा है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा की कार्ययोजना के अनुसार सभी कार्यक्रमों को संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) श्रीमती पूजा मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्रा, अपर नगर आयुक्त, उपजिलाधिकारी, एसीपी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिवस सेवा पखवाड़ा अभियान आज से होगा शुभारंभ

सेवा पखवाड़ा के सभी कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि होंगे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह होंगें

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के 75 वें वर्षगाठ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में सेवा पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ आज 17 सितंबर से होगा भाजपा प्रवक्ता राजेश केसरवानी जानकारी देते बताया कि सेवा पखवाड़ा अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा सुबह 7:45 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पार्क पर स्वच्छता अभियान चलाकर एवं उन्हें माल्यार्पण कर किया जाएगा

प्रवक्ता राजेश केसरवानी ने बताया इसके अलावा सुबह बालसन चौराहा के पास स्थित 8: 00 बजे भारद्वाज आश्रम में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और सुबह 8:20 बजे एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा एवं सुबह 11 बजे जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर लगे प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा और दोपहर 12:00 बजे रक्तदान शिविर का उद्घाटन अन्हा ब्लड बैंक जीएचएस स्कूल सिविल लाइंस में लगाया जाएगा और दोपहर 1:00 बजे दिव्यांग उपकरण वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन एनसीडीसी सांस्कृतिक केंद्र अशोक नगर के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा जिसमें दिव्यांग जनों को सम्मानित करते हुए उपकरण वितरित किए जाएंगे इन सभी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह होंगें।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल सेवा ऑपरेटरों की नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अगस्त 2025 के महीने के दौरान उत्तर प्रदेश पूर्व एल एस ए के कानपुर और उन्नाव शहर और प्रयागराज से लखनऊ के मध्यवर्ती राजमार्ग में इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट आयोजित किए थे । इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट को विभिन्न उपयोग क्षेत्रों - जैसे शहरी , हॉटस्पॉट, सार्वजनिक परिवहन केंद्र, आदि में वास्तविक दुनिया के मोबाइल प्रदर्शन को आंकने के लिए डिज़ाइन किया गया है ।

भा.दू.वि.प्रा. ने अपनी नियुक्त एजेंसी के माध्यम से, कानपुर और उन्नाव शहर में 356.1 किलोमीटर सिटी टेस्ट और 4.8 किलोमीटर वॉक टेस्ट और प्रयागराज से लखनऊ के मध्यवर्ती राजमार्ग में 196.8 किलोमीटर हाईवे ड्राइव टेस्ट 4 अगस्त से 8 अगस्त 2025 के बीच विस्तृत संपन्न किए। ड्राइव टेस्ट के दौरान, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम कार्डों के साथ मोबाइल एडवांस टेस्ट हैंडसेटों का उपयोग करके 2जी, 3जी, 4और 5नेटवर्क पर लाइव डेटा और वॉयस सेशन स्थापित किए गए थे।

भादूविप्रा TRAI

आईडीटी के निष्कर्षों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधित सेवा प्रदाताओं को प्रेषित कर दिया गया है।

प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का मूल्यांकन किया गया थाः क. वॉइस सेवाएंः कॉल सेटअप की सफलता दर, कॉल सेटअप का समय, मीन ओपिनियन स्को का उपयोग करके स्पीच क्वालिटी, कॉल साइलेंस दर, कवरेज-सिग्नल की शक्ति

ख. डेटा सेवाएँः डेटा थ्रूपुट (डाउनलिंक और अपलिंक दोनों), पैकेट ड्रॉप दर (डाउनलिंक और अपलिंक), वीडियो स्ट्रीमिंग में देरी, लेटेंसी, ज़िटर

कॉल सेटअप सफलता दरः एयरटेल, बीएसएनएल, आरजेआईएल और वीआईएल की ऑटो-सिलेक्शन मोड (5जी/4जी/3जी/2जी) में क्रमशः 98.23प्रतिशत, 96.31प्रतिशत, 100प्रतिशत और 98.71प्रतिशत की कॉल सेटअप सफलता दर है।

ड्रॉप कॉल दरः एयरटेल, बीएसएनएल, आरजेआईएल और वीआईएल में ऑटो-सिलेक्शन मोड (5जी/4जी/3जी/2जी) में क्रमशः 0.36प्रतिशत, 3.58प्रतिशत, 0.24प्रतिशत और 0.12प्रतिशत की ड्रॉप कॉल दर है।

महाप्रबन्धक नरेश पाल सिंह ने 11 रेल कर्मचारियों को किया पुरस्कृत

अमर सिंह एवं रजनी कान्त बने माह अगस्त 2025 के सर्वश्रेष्ठ रेलकर्मी

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। महाप्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, नरेश पाल सिंह द्वारा प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी, जे.सी.एस. बोरा एवं उत्तर मध्य रेलवे के विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में संरक्षा के प्रति किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए झाँसी, आगरा एवं प्रयागराज मण्डलों से अगस्त 2025 माह के लिए चयनित कुल 11 रेल कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार प्रदान किए गए।

पुरस्कृत कर्मचारियों में काली चरण, ट्रैक मेन्टेनर, बांदा, झाँसी मण्डल विक्रान्त बाबू राणा, कीमैन, कोसी कलां, आगरा मण्डल अंशुमान सिंह, प्वाइण्टस मैन, पनकीधाम/प्रयागराज मण्डल श्यामू पटेल, प्वाइण्टसमैन, प्रयागराज छिवकी/ प्रयागराज मण्डल भूरी सिंह, प्वाइण्टसमैन, हेतमपुर/ झाँसी मण्डल धरमपाल राजपूत, वरि. ट्रेन मैनेजर/वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी/झाँसी मण्डल राधा किशन, वरि. ट्रेन मैनेजर-गुड्स/ईदगाह/ आगरा मण्डल दीपक कुमार सुम्बरूई, लोको पायलट, प्रयागराज छिवकी/ प्रयागराज मण्डल करमेन्द्र कुमार सिंह, सहा. लोको पायलट, प्रयागराज छिवकी/प्रयागराज मण्डल अमर सिंह, लोको पायलट गुड्स, आगरा कैण्ट/आगरा मण्डल रजनी कान्त, सहा. लोको पायलट गुड्स, आगरा कैण्ट/आगरा मण्डल शामिल हैं।

अमर सिंह, लोको पायलट

गुड्स, आगरा कैण्ट/आगरा मण्डल एवं रजनी कान्त, सहायक लोको पायलट गुड्स, आगरा कैण्ट/आगरा मण्डल को संयुक्त रूप से 'माह का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी' के संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमर सिंह, लोको पायलट, मालगाड़ी, आगरा कैण्ट/आगरा मण्डल एवं रजनी कान्त, सहायक लोको पायलट, आगरा कैण्ट/आगरा मण्डल ने 24 जुलाई को गाड़ी सं. घ्ण्ऊ उद्दे पर कार्य के दौरान तुगलकाबाद-आगरा कैंट खण्ड में छाता-अझई स्टेशनों के मध्य अझई यार्ड में प्रवेश करते समय अचानक जर्क का अनुभव किया। क्रू द्वारा तुरंत गाड़ी को खड़ा किया तथा जर्क लगने वाले स्थान की जाँच करने पर रेल फ्रैक्चर पाया गया। इसकी सूचना सर्व सम्बंधित को दी। इस प्रकार इनकी सजगता एवं सतर्कता से एक संभावित रेल दुर्घटना को रोका गया।

आईवीएफ की क्या है असली लागत और पैकेज के अलावा आपको क्या-क्या जानना चाहिए?

मंत्र भारत संवाददाता

गोरखपुर। अधिकतर दंपत्ति आईवीएफ के बारे में सोचते हैं तो वह महीनों या सालों की इंतज़ार और सोच-विचार के बाद ही आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल जो वे आमतौर पर पूछते हैं, वह होता हैः 'इसका खर्च कितना होगा?' क्लिनिक्स आमतौर पर एक पैकेज प्राइस बताते हैं, जो शुरुआत में राहत देता है। डॉ. आकृति गुप्ता, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ, गोरखपुर बताते हैं कि. जैसे हर दंपत्ति की फर्टिलिटी स्टोरी अलग होती है, वैसे ही खर्च का रास्ता भी हमेशा एक जैसा नहीं होता। यह पहले से जानना, उन्हें सुरक्षित और फैसलों में सक्षम महसूस कराता है।

लगभग सभी आईवीएफ पैकेजेस के कुछ मूलभूत हिस्से हैं, जैसे - ओवेरियन स्टिमुलेशन, एग्ग रिट्रीवल, फर्टिलाइजेशन, और एम्ब्रियो ट्रांसफर। ज़्यादातर दंपत्तियों के लिए यह विकल्प बढ़िया होता है और बाद में सफलता प्राप्त हो जाती है।

कभी-कभी, दंपत्तियों को सफ़ल होने का पूरा मौक़ा देने के लिए अतिरिक्त स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए, इक्सी (जिसमें एक सिंगल स्पर्म को एग्ग में डाला जाता है), एम्ब्रियो फ्रीज़िंग, या जेनेटिक टेस्टिंग जैसे ट्रीटमेंट्स को उम्र, एग क्वालिटी, या पिछली ट्रीटमेंट हिस्ट्री के आधार पर सुझाया जा सकता है। ये सभी 'छिपे हुए खर्चे' नहीं है बल्कि व्यक्तिगत विकल्प हैं जो चिकित्सा जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने जाते हैं ताकि अधिकतम सफ़लता मिल सके।

आईवीएफ केवल एक ट्रीटमेंट्स का सेट नहीं है बल्कि यह एक शारीरिक और भावनात्मक अनुभव है। कुछ लोगों के लिए पूरी प्रक्रिया उबाऊ हो सकती है, कुछ में एक से ज़्यादा साइकल लग सकते हैं, और इसके लिए पहले से तैयार रहने पर आगे चलकर स्ट्रेस कम हो जाता है। जितना ज़रूरी मेडिकल ट्रीटमेंट है उतना ही ज़रूरी है उपलब्ध कराया गया काउंसलिंग और सपोर्ट, जो इसलिए बनाया गया है ताकि दंपत्तियों को कहीं भी अकेलापन महसूस ना हो।

Birla Fertility & IVF

सबसे सही तरीका वह होता है जिसमें दंपत्तियों को शुरू में ही शिक्षित किया जाएः बेस पैकेज क्या मौजूद है, कौन सा दूसरा ट्रीटमेंट सोचा जा सकता है, और कैसे ये सभी फ़ैसले सक्सेस रेट्स से जुड़े हुए हैं। दंपत्तियों को ऐसे क्लिनिक्स ढूढ़ने चाहिए जो पारदर्शी हैं ताकि वो बिना किसी असमंजस के स्पष्ट योजना बना सके।

अंततः आईवीएफ को एक लेन-देन सेवा की तरह कम और देखभाल, विज्ञान और सपोर्ट में निवेश की तरह ज़्यादा देखा जाना चाहिए। क़ीमत केवल पद्धतियों की नहीं बल्कि हर फ़ैसले का मार्गदर्शन करने वाली एक्सपर्टिज, लैब में मौजूद तकनीक, और दंपत्तियों को हर जगह संभालने वाली संवेदनशील काउंसलिंग का भी होता है। जब पेशेंट्स इस नज़रिए को समझने लगते हैं तब वो ट्रीटमेंट में अत्यधिक स्पष्टता और दृढ़ता के साथ कदम रखते हैं।

भाजपाइयों ने केक काट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 वे जन्म दिन की दी बधाई

फल एवं मिठाई बांटकर समाज एवं राष्ट्र सेवा का लिया गया संकल्प

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। भाजपा मुट्ठीगंज मंडल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर मुट्ठीगंज कार्यालय में मंडल अध्यक्ष परमानंद वर्मा के नेतृत्व में केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई इस अवसर प्रवक्ता राजेश केसरवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी एवं करोड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रेरणा स्रोत है और उनके जीवन से प्रभावित होकर समाज एवं राष्ट्र सेवा का संकल्प लेकर विकसित भारत निर्माण के लिए काम कर रहा।

इस अवसर पर मिठाई एवं फल वितरण किया गया और राष्ट्र एवं समाज सेवा का संकल्प लिया गया। संचालन सुधांशु त्रिपाठी ने किया। इस अवसर सुनील केसरवानी, अभिषेक जायसवाल, अजय अग्रहरि, आलोक वैश्य, शत्रुघ्न जायसवाल कमलेश केसरवानी, लवकुश केसरवानी, जितेंद्र जायसवाल, विनय जायसवाल, रिन्कू भारतीय विशाल मलिक , दीपक केसरवानी, नीरज केसरवानी, एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

291 अवैध इमारतें पालिका की नाक पर बदनामी का धब्बा

अधिकारी हुए मालामाल- कानून खा रहा है ठोकर

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी-निजामपुर शहर महानगर पालिका प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। वर्ष 2022 के बाद से शहर की हद में एक से छह मंजिला तक की कुल 291 अवैध इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। खुद पालिका आयुक्त अनमोल सागर (भा.प्र.से.) ने हाल ही में जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी थी। इसके बावजूद अब तक किसी भी इमारत पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थिति यह है कि अधिकांश अवैध इमारतों में रहिवासी बस चुके हैं और पालिका का टैक्स विभाग इनसे बाकायदा टैक्स वसूल कर रहा है। नगरवासियों का आरोप है कि टैक्स की वसूली से इन इमारतों को अप्रत्यक्ष रूप से वैधता का संरक्षण दिया जा रहा है। पिछले सप्ताह प्रशासन ने पांच अवैध निर्माणों पर आंशिक तोड़फोड़ की कार्रवाई कर कठोरता का प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन 291 इमारतों

पर अब तक बुलडोज़र नहीं चला। सूत्र बताते हैं कि टैक्स विभाग और विधि विभाग की ढिलाई से बिल्डरों को कोर्ट से आसानी से स्टे ऑर्डर मिल जाते हैं और अवैध निर्माण पूरे कर लिए जाते हैं। शहर में फिलहाल 150 से अधिक नए अवैध इमारतें तेज़ी से खड़े हो रहे हैं। सामाजिक संगठनों का आरोप है कि जब तक पालिका गंभीरता से कार्रवाई नहीं करती, तब तक अवैध निर्माण का यह सिलसिला थमता नजर नहीं आएगा। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता परमेश्वर अंभोरें का कहना है, 'नगरपालिका की मिलीभगत के कारण अवैध इमारतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भू-माफिया खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आम जनता की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है।' वही पर वार्ड अधिकारी भी जनप्रतिनियों के दबाव में आकार कुछ चिन्हित इमारतों पर ही कार्रवाई करते है। जिसके कारण लगातार अवैध इमारतों की संख्या में इजाफा हो रहा है।

इस मामले पर उपायुक्त (अतिक्रमण) विक्रम दराड़े ने कहा, 'पालिका प्रशासन अवैध इमारतों के विरुद्ध चरणबद्ध कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। जिन इमारतों पर स्टे ऑर्डर नहीं है, उन्हें जल्द ही ढहा दिया जाएगा। अभी तक निर्माणाधीन 15 अवैध इमारतों को निष्कासित किया जा चुका है। यही नहीं जब उनसे पूछा गया कि अवैध इमारतों पर स्लैब डाल रहे मिक्सर मशीन, आरसीएम मशीन पूर्व के भांति क्यों नही जब्त की जाती है। तब उन्होंने कहा कि पूर्व अधिकारी साकिब खर्च ऐसी मशीनरी जब्त किया करते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बहुत जल्द उचित कदम उठाया जायेगा।

भिवंडी में धार्मिक संगठनों की पहल, सात टन निर्माल्य हुआ इकट्ठा

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी में धार्मिक उत्सवों के दौरान जल प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक सराहनीय पहल सामने आई है। गणेश चतुर्थी और नवरात्रि जैसे पर्वों में बड़ी मात्रा में कचरा सीधे नदियों और तालाबों में डाला जाता रहा है। इससे जलस्रोतों के प्रदूषित होने की समस्या लगातार बढ़ रही थी। इसी पृष्ठभूमि में भिवंडी मनपा आयुक्त अनमोल सागर ने विभिन्न धर्मार्थ संगठनों से अपील की थी कि वे निर्माल्य संग्रह में आगे आएं।आह्वान पर पहल करते हुए डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के सदस्यों ने सक्रियता दिखाई और शहर के प्रमुख विसर्जन स्थलों पर विशेष अभियान चलाया। इसमें वाराल झील, कामतघर घाट, भादवड़ और तिलक घाट को केंद्र बनाया गया। अभियान के तहत गौरी-गणपति और अनंत चतुर्थी के अवसर पर केवल तिलक घाट से ही तीन टन निर्माल्य एकत्रित किया गया। वहीं वाराला देवी झील और कामतघर घाट पर मिलाकर चार टन अतिरिक्त कचरा जुटाया गया। कुल मिलाकर सात टन निर्माल्य एकत्रित कर उसे भादवड़ स्थित खाद निर्माण केंद्र तक पहुंचाया गया। सदस्यों ने इस दौरान विशेष ध्यान रखते हुए प्लास्टिक और अन्य गैर-अपघटनीय कचरे को अलग किया, ताकि केवल जैविक सामग्री खाद निर्माण में काम आ सके। गौरतलब है कि पूर्व में मनपा प्रशासन विसर्जन स्थलों पर कलश रखकर निर्माल्य एकत्रित करता था, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती थी। इस वर्ष जिम्मेदारी सीधे प्रतिष्ठान को सौंपे जाने के बाद संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

भिवंडी में नवरात्रोत्सव की तैयारी तेज

ॐ जय बाबा मित्र मंडल ने किया भूमिपूजन

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी।गणेशोत्सव की समाप्ति के साथ ही भिवंडी में नवरात्रोत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। शहर के श्रीरंग नगर स्थित रवि पाटिल कंपाउंड में मंगलवार को ॐ जय बाबा मित्र मंडल के सार्वजनिक नवरात्रोत्सव के पंडाल का भूमिपूजन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मां भक्त मौजूद रहे।मंडल के संस्थापक अध्यक्ष पत्रकार जितेंद्र तिवारी ने बताया कि पिछले 17 वर्षों से मंडल बंगाली पद्धति से भव्य नवरात्र जागरण उत्सव का आयोजन करता आ रहा है और इस वर्ष 18वां आयोजन धूमधाम से होगा। उत्सव के दौरान प्रतिदिन सुबह-शाम संगीतमय आरती, डांडिया व गरबा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक और जनजागृति से जुड़े उपक्रम भी शामिल रहेंगे।भूमिपूजन के दौरान समाजसेवक रवि पाटिल, विजय मिश्रा, राकेश केसरवानी, सुधाकर तिवारी, चंचल पांडेय समेत कई गणमान्य लोग तथा मंडल पदाधिकारी मौजूद रहे।

चाविंद्रा सिटी पार्क की आरक्षित जमीन पर कचरा डंपिंग ग्राउंड, नागरिकों के लिए बनी मुसीबत

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी-निजामपुर शहर महानगर पालिका क्षेत्र में कचरा प्रबंधन की समस्या लगातार गंभीर रूप ले रही है। शहर से रोजाना निकलने वाले हजारों टन कचरे को चाविंद्रा सिटी पार्क की आरक्षित जमीन पर बनाए गए डंपिंग ग्राउंड में डाला जा रहा है। इसके चलते आसपास के इलाकों–गायत्रीनगर, रामनगर, नूरीनगर और पोगांव चाविंद्रा–के नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है।स्थानीय लोगों का कहना है कि डंपिंग ग्राउंड से उठने वाली दुर्गंध और धुएं के कारण श्वसन रोग, चर्मरोग और अन्य बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। कचरे के ढेर में आए दिन आग लगने से वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि नागरिक अब आंदोलन की चेतावनी देने लगे है।नगरपालिका प्रशासन के अनुसार, शहर से रोजाना करीब 12 से 14 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। इसे डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाने का ठेका निजी कंपनियों को दिया गया है,स्थानीय लोगों की मांग है कि शहर के कचरे के निपटारे के लिए नया डंपिंग ग्राउंड बनाया जाए या वैज्ञानिक पद्धति से कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाए। इसी सिलसिले में गायत्रीनगर, पोगांव, चाविंद्रा और रामनगर क्षेत्र के नागरिकों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर पालिका आयुक्त अनमोल सागर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सुरेश पाटिल, अनंता पाटिल, संदीप पाटिल, सतीश पाटिल समेत भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

कोंकण रेलवे के सीएमडी संतोष कुमार झा के नये कविता संग्रह 'स्याही का सिपाही' का विमोचन

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई । हिंदी दिवस के अवसर पर गांधीनगर, गुजरात में आयोजित 5 वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संतोष कुमार झा के चौथे काव्य संग्रह ङ'स्याही का सिपाही'ङ का विमोचन किया गया। पुस्तक का विमोचन भारत सरकार के केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा, वैज्ञानिक डॉ. आनंद रंगनाथन और भारत सरकार की सचिव (राजभाषा) श्रीमती अंशुलि आर्या द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

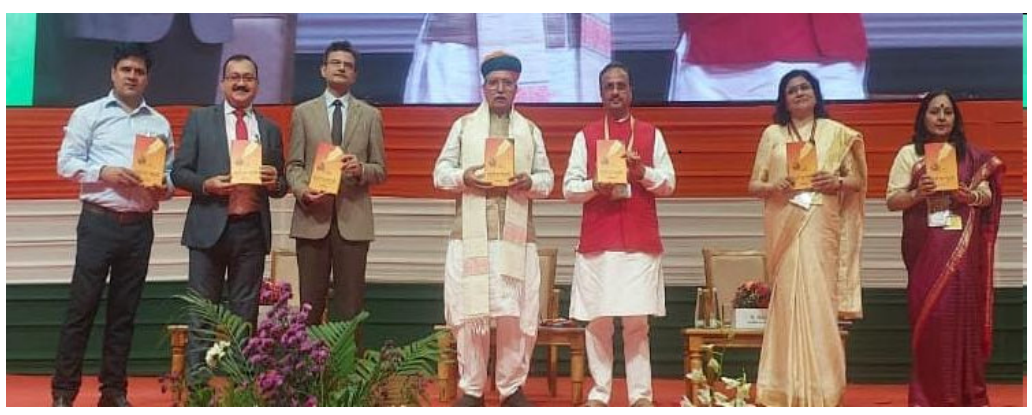

उल्लेखनीय है कि श्री संतोष कुमार झा एक अनुभवी प्रशासक और रेलवे के पेशेवर अधिकारी होने के साथ-साथ एक प्रख्यात कवि भी हैं। उनके तीन प्रकाशित कविता संग्रहों के साथ वे अपनी चिंतनशील और भावपूर्ण रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जिसके लिए महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और रेल मंत्रालय सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उनकी चौथी पुस्तक का विमोचन कोंकण रेलवे के कुशल नेतृत्व के साथ साहित्य के प्रति उनके समर्पण को बखूबी दर्शाता है। उनकी पिछली कृतियों ङ'उन्मुक्त'ङ, ङ'सूरज का वारिस'ङ और ङ'फूल, कलम और बंदूक'ङ के बाद ङ'स्याही का सिपाही'ङ उनकी साहित्यिक यात्रा को और सशक्त बनाती है। साथ ही उनके विशिष्ट पेशेवर करियर को और सुदृढ़ करते हुए रेलकर्मियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में समाज के विभिन्न स्तरों पर श्री झा को हार्दिक बधाई और अभिनन्दन का सिलसिला निरंतर जारी है।

18 सितंबर को होगा भिवंडी पालिका के प्रारूप प्रभाग रचना पर आपत्तियों की सुनवाई

भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका के सार्वत्रिक चुनाव 2025 की तैयारियाँ तेज हो गई हैं। महापालिका द्वारा प्रकाशित प्रारूप प्रभाग रचना पर नागरिकों की ओर से कुल 84 आपत्तियाँ और सुझाव दर्ज कराए गए हैं। ये हरकतें 3 से 15 सितंबर के बीच अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त हुईं। पालिका प्रशासन ने जानकारी दी है कि सभी 84 आपत्तियों की सुनवाई गुरुवार, 18 सितंबर 2025 को दोपहर 12 बजे होगी। यह सुनवाई महापालिका मुख्यालय की नई प्रशासनिक इमारत के तीसरे तल पर स्थित आयुक्त सभागार में आयोजित की जाएगी.सुनवाई की प्रक्रिया जिला अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी और प्रशासक/आयुक्त राधा विनोद शर्मा (भा.प्र.से.), मीरा-भाईंदर महानगरपालिका की उपस्थिति में संपन्न होगी। महापालिका ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों ने आपत्तियाँ या सुझाव डाक या टेलीफोन के जरिए भेजे हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। संबंधित हरकतदारों को पहचान पत्र व जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे और सुनवाई पूर्ण होने तक सभागार में मौजूद रहना होगा। इस प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति उप आयुक्त (निवडणूक) विक्रम दराडे ने जारी की है।

लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर के सम्मान में

भारतीय रेलवे ने अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'अहिल्यानगर' कर दिया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भारतीय रेलवे ने लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर के सम्मान स्वरूप, मध्य रेल के पुणे मंडल के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है।

यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने के निर्णय के अनुरूप भी है।

पहले अहमदनगर के नाम से जाना जाने वाला स्टेशन अब आधिकारिक रूप से अहिल्यानगर कर दिया गया है।

तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना और भारत के महासर्वेक्षक के पत्र के अनुसार, स्टेशन का नया नाम इस प्रकार पढ़ा और लिखा जाएगा:

देवनागरी लिपि (मराठी) में: अहिल्यानगर

देवनागरी लिपि (हिंदी) में: अहिल्यानगर

रोमन लिपि (अंग्रेजी) में:

स्टेशन कोड में कोई बदलाव नहीं होगा और अहिल्यानगर का स्टेशन कोर्ड'ङ ही रहेगा।

अमलनेर(बी) और अहिल्यानगर के बीच रेल सेवाएँ पहले से ही संचालित हैं।

अमलनेर(बी)-बीड नई रेल लाइन का उद्घाटन और बीड एवं अहिल्यानगर के बीच उद्घाटन ट्रेन को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिनांक 17.9.2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

बीड-अमलनेर(बी) खंड में 6 स्टेशन हैं

बीड, राजुरी (नवगण),रायमोहा, विघनवाड़ी,जतनांदूर, अमलनेर(बी)

यात्रियों और आम जनता से अनुरोध है कि वे इस बदलाव पर ध्यान दें।

IRCTC वेस्ट ज़ोन, मुंबई द्वारा विशेष अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेजों की घोषणा

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (IRCTC), जो कि रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक 'नवरत्न' सार्वजनिक उपक्रम है, ने मुंबई से शुरू होने वाले विशेष अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेजों की एक नई श्रृंखला की घोषणा की है। ये पैकेज यात्रियों को यादगार, सुविधाजनक और किफायती वैश्विक यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

घोषित अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेज निम्नलिखित लोकप्रिय गंतव्यों को कवर करते हैं:

जापान: 05-14 अक्टूबर 2025

भूटान: 31 अक्टूबर-05 नवम्बर 2025

थाईलैंड (फुकेट और क्राबी): 03-09 नवम्बर 2025

ऑस्ट्रेलिया: 11-22 नवम्बर 2025

श्रीरामायण यात्रा - श्रीलंका: 24-30 नवम्बर 2025

वियतनाम: 10-17 नवम्बर 2025

रहस्यमयी नेपाल: 23-28 दिसम्बर 2025

ये संपूर्ण समावेशी (ऑल-इंक्लूसिव)

पैकेज में यात्रियों के लिए आने-जाने का हवाई यात्रा किराया, आरामदायक आवास व्यवस्था, सभी समय का भोजन, गाइडेड साइटसीइंग, लोकल ट्रांसफर, एंट्री टिकट शुल्क, वीज़ा/अनुमति सहायता, ट्रैवल इंश्योरेंस एवं जीएसटी सहित सुविधाएं शामिल हैं, इससे यात्रियों को बिना किसी चिंता के संपूर्ण यात्रा का आनंद मिलता है और उन्हें बेहतर मूल्य के साथ शानदार अनुभव प्राप्त होता है।

गौरव झा, समूह महाप्रबंधक, IRCTC वेस्ट ज़ोन, मुंबई ने कहा: कि 'ये पैकेज आराम, गुणवत्ता और किफायती मूल्य का आदर्श संतुलन प्रदान करते हैं। हर यात्रा कार्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यात्री समृद्ध अनुभवों और मधुर यादों के साथ लौटें।'

IRCTC के अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेजों को हमेशा यात्रियों से शानदार प्रतिसाद मिला है। नियमित ग्राहक अक्सर इनकी घोषणा होते ही बुकिंग कर लेते हैं। बाज़ार में उपलब्ध अन्य विकल्पों की तुलना में, IRCTC के पैकेज प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, उत्तम आतिथ्य और सुनियोजित कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध हैं।

यात्री निम्नलिखित माध्यमों से आसानी से बुकिंग कर सकते हैं:

IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट: www.irctctourism.com

देशभर में अधिकृत ट्रैवल एजेंट

व्हाट्सएप या एसएमएस द्वारा सहायता: 8287931886

इन विशेष रूप से तैयार किए गए अंतरराष्ट्रीय पैकेजों के माध्यम से, IRCTC अपने मिशन–भारतीय यात्रियों के लिए वैश्विक यात्रा को सुलभ और अविस्मरणीय बनाने–को आगे बढ़ा रहा है।

विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के बाद जैसमीन और मीनाक्षी की नजरें लॉस एंजिलिस ओलंपिक पर

नई दिल्ली। लॉस एंजिलिस 2028 ओलंपिक में तीन साल से भी कम समय बचा है और ऐसे में स्टार भारतीय मुक्केबाज जैसमीन लंबोरिया ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में लिवरपूल में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब वह अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल खेलों के महाकुंभ की तैयारी के लिए करेंगी।

जैसमीन ने 57 किग्रा वर्ग के फाइनल में पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता जूलिया सेरेमेटा को हराकर पदक के अपने लंबे इंतजार को खत्म किया। जैसमीन साथी स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी हुड्डा, निकहत जरीन और नूपुर श्योराण सहित टीम की अन्य साथियों सहित यहां पहुंचीं। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने विदेशी धरती पर विश्व चैंपियनशिप में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

विश्व चैंपियनशिप में तीसरे प्रयास में सफलता हासिल करने वाली 24 वर्षीय जैसमीन ने कहा, ''यह अच्छा लगता है और स्वर्ण पदक जीतना अपने आप में बेहद खुशी की बात है। मेरे कोच ने मेरे खेल को बेहतर बनाने में मेरी बहुत मदद की है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं।''

दिग्गज भारतीय मुक्केबाज और एशियाठ खेलों के दो बार के स्वर्ण पदक विजेता हवा सिंह की रिश्तेदार जैसमीन ने कहा, ''मैं

दो बार पदक से चूक गई लेकिन अब मैंने स्वर्ण पदक के साथ वापसी की है इसलिए यह बहुत संतोषजनक है। हां, प्रशिक्षण उसके (ओलंपिक पदक) लिए होगा और मेरे कोच मेरी तकनीकी ट्रेनिंग पर उसी के अनुसार काम करेंगे।''

जैसमीन के कोच संदीप लंबोरिया ने लॉस एंजिलिस में उनके पदक जीतने का भरोसा जताया।

संदीप ने कहा, ''यह (प्रदर्शन) शानदार था। हमारा मुख्य लक्ष्य लॉस एंजिलिस 2028 ओलंपिक है। वह ओलंपिक भार वर्ग में पदक जीतने वाली एकमात्र लड़की है। वह 2028 में धूम मचाएगी।'' विश्व चैंपियनशिप में 48 किग्रा वर्ग के फाइनल में पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता कजाखस्तान की नाजिम काइजेबे को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली मीनाक्षी ने कहा कि उनकी नजरें नवंबर में भारत में होने वाले विश्व कप पर टिकी हैं। मीनाक्षी ने विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण किया था। मीनाक्षी ने कहा, ''विश्व कप नवंबर में भारत में होगा और मैं वहां भी स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना चाहती हूं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता और मुझे अपने कौशल पर काम करना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। हार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।'' उन्होंने कहा, ''जीतने के बाद आप कुछ दिनों के लिए खुश रहते हैं लेकिन हार से बहुत कुछ सीखते हैं। यह मेरी पहली विश्व चैंपियनशिप थी। मैं बहुत खुश हूं।''

लिवरपूल में रजत पदक जीतने वाली नूपुर ने कहा कि भारत के दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य सहित चार पदक जीतने से टीम को विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास मिला है। नूपुर ने कहा, ''वहां हमारा अनुभव अच्छा रहा। भारत कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर रहा। हमने चार पदक जीते। अब भारत नवंबर में विश्व कप की मेजबानी करेगा और हम देश के लिए अधिक से अधिक पदक जीतने की कोशिश करेंगे।''

कांस्य पदक जीतने वाली पूजा रानी (80 किग्रा) ने कहा कि हवाई अड्डे पर दल को मिले सम्मान से वह अभिभूत हैं। पूजा ने कहा, ''इतने सारे लोग हमारा स्वागत करने आए हैं। हमें इतना सम्मान मिला है। यह मेरी चौथी विश्व चैंपियनशिप थी। मुझे पहली बार पदक मिला है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। हम भविष्य में और बेहतर करेंगे।'' शीर्ष भारतीय मुक्केबाज और विश्व चैंपियनशिप की दो बार की स्वर्ण पदक विजेता निकहत जरीन ने कहा कि पदक चूकने की निराशा के बावजूद वह कड़ी मेहनत जारी रखेंगी।

निकहत ने कहा, ''मेरा मंत्र हमेशा कड़ी मेहनत करना रहा है, चाहे मेरे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं। इस विश्व चैंपियनशिप में मैं तुर्की की नंबर एक मुक्केबाज से क्वार्टर फाइनल में हार गई। मुझे कोई पछतावा नहीं है।'' उन्होंने कहा, ''मुझे पता है कि मेरी तैयारी ठीक नहीं थी लेकिन मैं अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हूं। विश्व चैंपियनशिप हर साल होती है। मैं निराश और दुखी नहीं होना चाहती। कोई बात नहीं। मैं और मजबूत होकर वापसी करूंगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी।''

निकहत ने कहा, ''मेरा एकमात्र लक्ष्य लॉस एंजिलिस में ओलंपिक पदक जीतना है। मुझे खुद पर भरोसा बनाए रखना है। पेरिस तो चला गया। मेरा अगला लक्ष्य लॉस एंजिलिस है।

वैशाली रमेशबाबू ने लगातार दूसरी बार फिडे ग्रैंड स्विस का जीता खिताब, पीएम मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली।भारतीय ग्रैंडमास्टर वैशाली रमेशबाबू ने सोमवार को पूर्व महिला वर्ल्ड चैंपियन टैन झोंगयी के खिलाफ अपना अंतिम गेम ड्रॉ खेलकर फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट जीत लिया है। ये पहली बार है जब किसी खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट को दो बार जीता है। इस जीत के साथ वैशाली ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली है। वह अब कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बाद कैंडिडेट्स के लिए क्वालीफाई करने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं।

वहीं वैशाली की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारत के पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि, शानदार उपलब्धि। वैशाली रमेशबाबू को बधाई। उनका जुनून और समर्पण अनुकरणीय है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।

पाकिस्तान की निकली हेकड़ी, एशिया कप का बॉयकॉट नहीं करेगा, यूएई में ही रहेगी टीम

आबूधाबी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग को लेकर एशिया कप 2025 का बॉयकॉट करने की धमकी दी थी। जिसके बाद आईसीसी ने उनकी डिमांड को रद्द कर दिया। जिसके बाद पीसीबी की हेकड़ी निकल गई है। कहा जा रहा है कि, पाकिस्तान अब कहीं नहीं जाएगा। पाकिस्तानी टीम यूएई में ही रहेगी और एशिया कप के अन्य मुकाबले भी खेलेगी।

ईएसपीएन क्रिकन्फो की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं करेगा। इसका मतलब है कि 17 सितंबर को पाकिस्तान मेजबान यूएई से

भिड़ेगा। ग्रुप ए से भारत पहले ही सुपर-4 के लिए क्वालीफाई करचुका है ऐसे में बुधवार का मैच बहुत अहम है। पाकिस्तान या यूएई में ये जो भी ये मैच जीतेगा, सुपर-4 के लिए उसका दावा मजबूत हो जाएगा।

इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट की शिकायत की थी। बोर्ड ने उन्हें एशिया कप से तत्काल हटाने की मांग की थी। पीसीबी अधिकारियों ने धमकी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप का बहिष्कार करेगा। आईसीसी ने मंगलवार को पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी।

पूरे मामले में शुरुआत 14सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान मैच से हुई। टॉस के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। एकतरफ मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और सभी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के क्रिकेटरों से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हेसन भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए इंडियन ड्रेसिंग रूम की तरफ भी गए, लेकिन उसका दरवाजा बंद हो गया। इससे बौखलाए पाकिस्तान के कप्तान आगा ने पोस्ट मैच प्रजेंटेशन का बहिष्कार किया।

टीम इंडिया को मिला नया स्पॉन्सर, अपोलो टायर्स के साथ हुआ करार

नई दिल्ली। ड्रीम-11 के बाद भारतीय क्रिकेट की नया जर्सी स्पॉन्सर मिल गया है। दरअसल, टीम इंडिया की जर्सी पर अब अपोलो टायर्स का नाम छपेगा। अपोलो टायर्स का बीसीसीआई के साथ 2027 तक के लिए करार हुआ है। बीसीसीआई की ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ड्रीम-11 के साथ डील रद्द होने के बाद नए टाइटल स्पॉन्सर की घोषणा हुई। भारतीय पुरुष टीम फिलहला एशिया कप 2025 में बगैर स्पॉन्सर के खेल रही है।

अपोलो टायर्स बीसीसीआई को एक मैच के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा, जो ड्रीम-11 की तुलना में ज्यादा है। ड्रीम-11 बीसीसीआई को प्रति मैच 4 करोड़ रुपये का भुकतान करता

था। भारत का इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल काफी बिजी रहने वाला है जिससे नए स्पॉन्सर को वैश्विक स्तर पर अहम पहचाना मिलेगी। भारत को साल 2027 तक तकरीबन 130 मैच खेलने हैं। हालांकि, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि आगामी महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जर्सी पर नए स्पॉन्सर का नाम होगा या नहीं। ये टूर्नामेंट 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका की सयुंक्त मेजबानी में आयोजित होगा।

बता दें कि, ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 के प्रचार और विनियमन के पारित होने के बाद बीसीसीआई और ड्रीम-11 का करार रद्द हुआ। बीसीसीआई का ड्रीम-11 के साथ 358 करोड़ रुपे प्रति वर्ष का करार था। पिछले महीने, संसद ने पैसे के जरिए खेले जाने वाले सभी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने और ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पारित किया। ये कानून ऑनलाइन मनी गेम से संबंधित विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाता है, साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी गेम के लिए धन उपलब्ध कराने या हस्तांतरित करने से रोकता है।

भारतीय टेनिस की मदद के लिए सिर्फ पद पर काबिज होना ही एकमात्र रास्ता नहीं है : सानिया

दुबई **(एजेंसी)**। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के अनुसार देश के प्रत्येक खेल महासंघ की 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति में चार महिलाओं का होना अनिवार्य है लेकिन दिग्गज खिलाड़ी सानिया मिर्जा का मानना है कि युवा प्रतिभाओं को तराशने में उनकी भूमिका अखिल भारतीय टेनिस संघ में एक पद से कहीं अधिक है। खेलों में भारतीय महिलाओं के लिए पथ प्रदर्शक रहीं सानिया ने अपने दुबई स्थित आवास से पीटीआई से कई मुद्दों पर बात की जिनमें टेनिस में वेतन समानता से लेकर स्विट्जरलैंड के खिलाफ भारत की डेविस कप जीत शामिल रहीं जबकि उन्होंने 16 साल की माया राजेश्वरन रेवती की विशेष प्रतिभा पर भी बात की है।

यह पूछे जाने पर कि क्या वह निकट भविष्य में खेल प्रशासन में दिखाई दे सकती हैं तो सानिया ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि मदद करने के लिए उस शक्तिशाली पद पर होना ही एकमात्र तरीका है। ईमानदारी से कहूं तो मेरा यही जवाब है। अगर मुझे मौका मिले तो क्या मैं कर पाऊंगी, तो क्या मैं उस पद पर रहकर और योगदान दे पाऊंगी तो मैं ऐसा करना पसंद करूंगी। लेकिन क्या मैं इसका लक्ष्य बना रही हूं तो मेरा जवाब है, नहीं।

क्योंकि यह मेरा लक्ष्य नहीं है।'

सानिया के लिए भारतीय टेनिस की अगली पीढ़ी के स्तर को बढ़ाने में मदद करने के लिए कोई पद पर बैठना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा, ''मेरा लक्ष्य युवा पीढ़ी के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों और विशेषकर युवा लड़कियों की मदद करना है क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास ज्यादा आदर्श नहीं हैं जिनसे वे प्रेरणा ले सकें।'

सानिया ने कहा, 'मैं अपने अनुभव साझा करना चाहती हूं। और अगर मुझे इसके लिए किसी तंत्र में शामिल होने का मौका मिलता है और इससे मुझे सिर्फ फोन पर बात करने या कोर्ट पर उनकी मदद करने या किसी भी तरह की अन्य चीज से ज्यादा मौके मिलते है तो मुझे ऐसा करने में खुशी होगी।' उन्होंने कहा, 'लेकिन मेरा फोकस इस पर नहीं है। यह मेरा लक्ष्य नहीं है।'

सानिया के बाद भारत में महिला टेनिस में कौन उभरती हुई प्रतिभा है, यह पूछने पर उन्होंने माया राजेश्वरन रेवती का नाम लिया । माया स्पेन में राफेल नडाल अकादमी में ट्रेनिंग लेती हैं। सानिया ने कहा, 'माया में काफी प्रतिभा है। मेरे बाद कौन आएगा, यह ऐसा सवाल है जिससे हम शायद पिछले 25 साल से जूझ रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'तो एक 15-16 साल की युवा खिलाड़ी को आगे बढ़ते हुए देखना और अपने आयु वर्ग के ऊपर वर्गों में भी अपनी पकड़ बनाए रखते हुए देखना अच्छा लगता है।'

एकल में पूर्व 27वें नंबर की खिलाड़ी सानिया ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ डेविस कप मुकाबला जीतने के लिए भारतीय पुरुष टीम की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, 'डेविस कप टीम तारीफ की हकदार है जिसने यूरोप में शायद 31 या 32 साल बाद स्विट्जरलैंड को हराकर एक यूरोपीय टीम के खिलाफ पहली बार जीत हासिल की है। सुमित नागल ने अच्छा नेतृत्व किया और पिछले डेढ़ साल में एक तरह से शानदार वापसी की है।'

नागल के बारे में बात करते हुए सानिया ने कहा कि भारत का शीर्ष एकल खिलाड़ी अभी 28 साल का है। उन्होंने कहा, 'लेकिन यह खिलाड़ी अब उतना युवा नहीं है। ये खिलाड़ी 28, 29, 30 साल के हैं। और टेनिस के लिहाज से ये इतने युवा नहीं हैं। यही सच है। लेकिन सुमित ने पिछले कुछ सालों से अकेले ही अविश्वसनीय काम किया है और डेविस कप में भी जीत हासिल की है।'

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

सीएच.ई. (एस.ओ.) विभाग

क्रमांकः सं. ई.ई.एम./सीव/3938 सिटी-1 दिनांक 15.09.2025

ई-निविदा सूचना

ग्रेटर मुंबई नगर आयुक्त निम्नलिखित ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करते हैं। निविदा की प्रति महाटेंडर पोर्टल (https://mahatenders.gov.in/nicgep/app) से 'सी-प्रोक्योरमेंट' अनुभाग के अंतर्गत डाउनलोड की जा सकती है।

अ.क्र.	कार्य विवरण	निविदा संदर्भ संख्या	ईएमडी रु.	निविदा शुल्क रु.	टेंडर जारी है
1.	दादर सीवेज प्रयोगशाला में 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्लेषणात्मक सेवाएँ प्रदान करना।	2025_ एमसीजीएम_ 1218509_1	13,100/-	3,630/- (प्लस 18% जीएसटी)	30.09.2025 04.00 PM

अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें: https://mahatenders.gov.in/nicgep/app

(पी. ए. सालगांवकर)

पीआरओ/1609/विज्ञा./2025-26 कार्यकारी इंजीनियर, यांत्रिकी (स्क्वायर) शहर-I

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

वृक्ष प्राधिकरण

-सार्वजनिक सूचना-

महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण एवं परिरक्षण अधिनियम, 1975 (जनवरी 2018 तक संशोधित) की धारा 8 (3) (सी) के प्रावधानों के अनुसार, जोन-V के 'एल' वार्ड से 1 प्रस्ताव, 'एम/पश्चिम' वार्ड से 1 प्रस्ताव और जोन-VI के 'एस' वार्ड से 1 प्रस्ताव, अर्थात् कुल 3 वृक्षों को हटाने के प्रस्तावों को नगर आयुक्त, अध्यक्ष, वृक्ष प्राधिकरण, बीएमसी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा (8) की उपधारा (6) के अंतर्गत अनुमोदित किया जाता है।

उपर्युक्त प्रस्तावों में काटे जाने/रोपण हेतु वृक्षों की जानकारी बीएमसी वेबसाइट - https://portal.mcgm.gov.in/ पर उपलब्ध है। हमारे बारे में: वार्ड/विभाग नियमावली/उद्यान एवं वृक्ष प्राधिकरण। 60 (एल), 61 (एम/डब्ल्यू) और 62 (एस)।

अधीक्षक उद्यान एवं वृक्ष अधिकारी
अधीक्षक कार्यालय. उद्यान एवं वृक्ष अधिकारी,
दूसरी मंजिल, हम्बोल्ट पेंगुइन बिल्डिंग,
वी.जे.बी बॉटनिकल उद्यान एवं चिड़ियाघर, संत। सावता माली मार्ग,
भायखला (पूर्व), मुंबई-400 027
दूरभाष. क्रमांक 23742162
ईमेल-sg.gardens@mcgm.gov.in

पीआरओ/1612/विज्ञा./2025-26 उद्यान अधीक्षक एवं वृक्ष अधिकारी

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

महाराष्ट्र शासन
इलाखा शहर विभाग, (सा.बां.)

ई-निविदा सुचना क्र. 44 सन 2025-2026

कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई (दुरध्वनी क्रमांक-२२०१६९७५ /२२०१६९७७) महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे योग्य वर्गातील नोंदणीकृत कंत्राटदाराकडून खालील कामाकरीता ब-१ नमुन्यातील निविदा ई-निविदा प्रणालीव्दारे (ऑनलाईन) मागवित आहेत. निविदा स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई यांनी राखून ठेवला आहे.

अ.क्र.	कामाचे नाव	अंदाजित रक्कम रू. लक्ष
१.	सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस मुंबई येथील व्हुकटर, एसीपी, फॉल्स सिलींग, रंगकाम व इतर कामे करणे.	१८.१३
२.	मलबार हिल मुंबई येथील तोरणा बंगला स्टाफ क्वाटर्स येथे प्रसाधनगृह, खिडक्या, एसीपी शिट, पार्टीशन, पॅनलिंग, फ्लोरींग, फॉन्स सिलींग इ दुरुस्ती व नुतनीकरण करणे.	१९.८६
३.	मंत्रालय मुंबई मुख्य इमारत ६ मजल्यावरील कॅबीनेट हॉल वुडन कारपेट येथे नुतनीकरण करणे.	१३.२५
४.	एल.टी. मार्ग मुंबई येथील मुख्य इमारत कमिशनर ऑफ पोलिस ऑफिस येथे दुरूस्ती व वार्षिक देखभाल करणे.	२५.३६
५.	नविन सिटी सिव्हील कोर्ट इमारत मुंबई येथील दरवाजा, खिडक्या, लाकडी वस्तु, सॅनिटरी, पाईप लाईन, प्लास्टर, रंगकाम व वार्षिक देखभाल व दूरुस्ती करणे.	११.३१
६.	नविन विधानभवन मुंबई येथील डोम व टॉवर इमारत येथील तळमजला ते ३ मजल्यावरील फ्लोरींग, पार्टीशन, फॉल्स सिलींग, दरवाजा, खिडक्या, पार्टीशन, पॅनलिंग हॉल व विविध कार्यालय येथे दुरुस्ती व नुतनीकरण करणे.	३२.६९
७.	मंत्रालय मुंबई मुख्य इमारत ६ मजल्यावरील सी.एम ऑफिस ॲडिशनल चिफ सेक्रेटरी येथे नुतनीकरण करणे.	२०.७७
८.	एल.टी. मार्ग मुंबई येथील कॉन्स्टेबल क्वार्टर्स बी व सी ब्लॉक येथे दुरूस्ती व वार्षिक देखभाल करणे.	१६.३७
९.	नविन विधानभवन मुंबई येथील सेंट्रल हॉल येथील टाउन इमारत पॅनलिंग, फॉल्स सिलींग कमिटीरुम विविध मजल्यावरील तसेच असेंबली काउंसील हॉल, लॉबी पोर्शन, साईड पॅनलिंग इ. नुतनीकरण करणे.	२०.२१
१०.	मलबार हिल मुंबई येथील अंवती अंबर इमारत येथील पाण्याची टाकी, स्टोर रूम, अंतर्गत टाकी येथे दुरूस्ती करणे.	१६.०७
११.	एन.डी. रोड मलबार हील मुंबई येथील रॉकी हिल टॉवर इमारत ए-विंग येथे विविध सदनिकांचे अंतर्गत प्लास्टर च रंगकाम करणे.	१५.५५
१२.	नविन विधानभवन मुंबई येथील सेंट्रल हॉल येथील पॅनलिंग लॉबी इ. दुरुस्ती करणे.	९.९८
१३.	मलबार हिल मुंबई येथील वर्षा बंगला येथे प्लास्टर व रंगकाम करणे.	१९.८७
१४.	मंत्रालय मुख्य इमारत मुंबई येथील त्रीमुर्ती चौक रूफ टॉप येथे सिलीकॉन रूफ टॉप क्लिनिंग लॅमिलेट ग्लास इ. काम करणे.	८.७७
१५.	एल.टी. मार्ग मुंबई येथील सी.पी. ऑफिस आवर जुनी इमारत कमिशनर ऑफ पोलीस येथे वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती करणे.	२४.७१
१६.	पी डीमलो रोड मुंबई येथील कंमाडो आणि कॉन्सेटबल क्वार्टस इमारतीचे ड्रेनेज लाईन, चेंबर, गल्ली ट्रॅप दुरुस्ती नुतनीकरणकरणे.	२४.२१
१७.	हाजी अली शासकीय वसाहत मुंबई येथील इमारत नं. ११ क्वाटर्स अ-३ प्रसाधनगृह, फ्लोरींग, कपबोर्ड किचन, दरवाजा, खिडक्या, ग्रील इ. दुरुस्तीची कामे व नुतनीकरण करणे.	१५.०९
१८.	चर्चगेट मुंबई येथील आसावरी व विभावरी इमारत येथे दुरूस्ती व वार्षिक देखभाल करणे	३१.५५

ई-निविदा उपलब्ध कालावधी दि. १७.९.२०२५ ते दि. २४.९.२०२५ पर्यंत.
ई-निविदा उघडणे - दि. २५.९.२०२५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता
निविदा सुचने मध्ये काही बदल/सुधारणा करावयाची असल्याचे शुध्दीपत्रक वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात येणार नाही. त्याबत सर्व बदल ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेमध्ये प्रसिध्द केले जाईल.
खालील संकेतस्थळावरुन ई-निविदाची सर्व माहीती उपलब्ध आहे.
१) www.mahapwd.com
२) http://mahatenders.gov.in

जा.क्रं. इशवि/निलि/९४८१
कार्यकारी अभियंता
इलाखा शहर विभाग, मुंबई यांचे कार्यालय,
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,
२ रा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, फोर्ट,
मुंबई- ४०० ००१.
Email: presidency.ee@mahapwd.gov.in
दिनांक : ११.०९.२०२५

(व्ही.ए. पाटसकर)
कार्यकारी अभियंता
इलाखा शहर विभाग, मुंबई

DGIPR/2025-26/2574

उत्तराखंड में जल प्रलय का कहर! देहरादून में टपकेश्वर मंदिर जलमग्न, सड़कें टूटीं, कई लापता

देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में भारी बारिश के कारण तमसा नदी उफान पर आ गई और शहर के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक, टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया। बढ़ता जलस्तर मंदिर की गुफा में घुस गया और शिवलिंग डूब गया। पानी मंदिर प्रांगण में भी घुस गया और हनुमान जी की मूर्ति तक पहुँच गया, हालाँकि गर्भगृह सुरक्षित रहा। देहरादून सिटी बस स्टैंड से लगभग 5.5 किलोमीटर दूर, गढ़ी कैंट क्षेत्र में एक छोटी नदी के किनारे स्थित टपकेश्वर मंदिर तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है। मंदिर की एक अनूठी विशेषता गुफा के अंदर स्थित शिवलिंग है, जिस पर ऊपर की चट्टान से लगातार पानी की बूँदें गिरती रहती हैं, इसलिए इसका नाम टपकेश्वर पड़ा। इस मंदिर में भारी भीड़ उमड़ती है, खासकर शिवरात्रि मेले के दौरान, जब भक्त पूजा-अर्चना के लिए इकट्ठा होते हैं।

मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित हैः मंदिर के पुजारी

एएनआई से बात करते हुए, मंदिर के पुजारी आचार्य बिपिन जोशी ने कहा कि सुबह से ही नदी का बहाव तेज़ था और पूरा मंदिर परिसर जलमग्न हो गया था। उन्होंने कहा, 'सुबह 5 बजे से ही नदी का बहाव तेज़ हो गया था और पूरा मंदिर परिसर जलमग्न हो गया था... ऐसी स्थिति बहुत लंबे समय

से नहीं आई थी... कई जगहों पर नुकसान हुआ है... लोगों को इस समय नदियों के पास जाने से बचना चाहिए... मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित है... अभी तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है...'

स्थानीय निवासियों ने भी गुफा मंदिर के अंदर पानी के बढ़ने का अपना अनुभव साझा किया। एक स्थानीय निवासी ने एएनआई को बताया कि जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है और यह 10-12 फीट तक बढ़ गया है। उन्होंने आगे बताया, 'सुबह करीब 4:45 बजे पानी गुफा में घुस गया... बाद में जब जलस्तर बढ़ने लगा तो यह 10-12 फीट तक बढ़ गया... पानी 'शिवलिंग' के ऊपर तक पहुंच गया... किसी तरह हमने अपना रास्ता बनाया और रस्सी की मदद से हम ऊपर आ गए...'

उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही

उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर रातभर हुई भारी बारिश से सड़कें, मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं तथा मंगलवार तड़के एक पुल बह गया। इस आपदा के बाद कई लोगों के लापता होने की खबर है, तथा कुछ स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि देहरादून में सहस्त्रधारा और मालदेवता तथा मसूरी से भी नुकसान की खबरें मिली हैं। देहरादून में दो से तीन लोग लापता बताए जा रहे हैं। मसूरी में एक व्यक्ति की मौत की खबर मिली है और इसकी पुष्टि की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं, वहीं 300 से 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

टिहरी में जलभराव

आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि टिहरी में जलभराव के कारण गीता भवन में लोग फंस गए थे जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसके अलावा भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के मलबे से नैनीताल में एक सड़क आवागमन के लिए बंद हो गई है। वहीं मझारा गांव के निवासी सड़कों पर इकट्ठा हैं और उनका कहना है कि वे भूस्खलन से बाल बाल बचे हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग लापता हो गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "कल देर रात देहरादून के सहस्त्रधारा में भारी बारिश के कारण कुछ दुकानों के क्षतिग्रस्त होने का दुखद समाचार मिला। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस बल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं।

हिन्दी पखवाड़ा के अंतर्गत आयुर्वेद दिवस गंगा नाथ झा परिसर प्रयागराज में एक दिवसीय वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन

प्रयागराज। विश्व आयुर्वेद मिशन एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, गंगा नाथ झा परिसर, प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में आयुर्वेद दिवस समारोह की श्रृंखला में हिन्दी पखवाड़ा के अन्तर्गत भारतीय ज्ञान परम्परा एवं आयुर्वेद विषय पर एक दिवसीय वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन दि. 17 सितम्बर,2025 को अपराह्न 3 बजे गंगा नाथ झा परिसर, आज़ाद उद्यान में आयोजित है । जिसकी अध्यक्षता परिसर निदेशक प्रो. ललित कुमार त्रिपाठी करेंगे । सारस्वत अतिथि के रूप में हिन्दी के प्रख्यात साहित्यकार एवं वैश्विक हिन्दी महासभा के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ विजयानंद, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ केएन उपाध्याय, प्राचार्य राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हण्डिया, डॉ शांति चौधरी, पूर्व शोध अधिकारी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं डॉ मनोज कुमार सिंह, क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी, प्रयागराज उपस्थित रहेंगे । उक्त कार्यक्रम में विश्व आयुर्वेद मिशन के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रो (डॉ) गिरीन्द्र सिंह तोमर मुख्य वक्ता के रूप में उद्बोधन देंगे । यह संगोष्ठी प्रो अपराजिता मिश्रा के संयोजकत्व में सम्पन्न होगी । यह जानकारी कार्यक्रम के आयोजन सचिव एवं विश्व आयुर्वेद मिशन के सह सचिव डॉ अवनीश पाण्डेय ने दी है ।

राजनाथ सिंह का आह्वानः सेना बनेगी 'टेक-फ्रेंडली', भविष्य के युद्धों की तैयारी तेज

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों से युद्ध की पारंपरिक अवधारणाओं से आगे बढ़कर सूचना, वैचारिक, पारिस्थितिक और जैविक युद्ध जैसे अपरंपरागत खतरों से उत्पन्न अदृश्य चुनौतियों से निपटने के लिए सतर्क और तैयार रहने का आह्वान किया है। 16 सितंबर को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री ने अशांत वैश्विक व्यवस्था, क्षेत्रीय अस्थिरता और उभरते सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए, दुनिया भर में हो रहे बदलावों और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर उनके प्रभाव के निरंतर आकलन की आवश्यकता पर बल दिया।

राजनाथ सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि युद्ध की प्रकृति लगातार विकसित हो रही है, और हाल के वैश्विक संघर्षों ने एक 'प्रौद्योगिकी-अनुकूल' सेना की प्रासंगिकता को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि आज के युद्ध इतने अचानक और अप्रत्याशित होते हैं कि उनकी अवधि का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। यह दो महीने, एक साल या पाँच साल भी हो सकता है। हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हमारी क्षमता पर्याप्त बनी रहे।

भारत के रक्षा क्षेत्र को आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का सम्मिश्रण बताते हुए, रक्षा मंत्री ने कमांडरों से सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने और प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना के अनुरूप सुदर्शन चक्र के निर्माण के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि परियोजना की जाँच और एक 'यथार्थवादी कार्य योजना' तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अगले पाँच वर्षों के लिए एक मध्यम अवधि और अगले दस वर्षों के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाने का सुझाव दिया।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि देश का रक्षा क्षेत्र आधुनिकीकरण, परिचालन तत्परता, तकनीकी श्रेष्ठता और विश्वसनीय प्रतिरोध पर केंद्रित है, राजनाथ सिंह ने 15 सितंबर, 2025 को सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए 'जय (संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार)' के मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। सिंह ने भविष्य के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों के विकास में उद्योग और शिक्षा जगत के साथ गहन जुड़ाव की वकालत की। उन्होंने एक मजबूत रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और घरेलू उद्योग को दुनिया में सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ बनाने में निजी क्षेत्र की भूमिका को और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण की पुष्टि की।

'विकास नहीं विनाश कर रहा मास्टर प्लान', हरिद्वार में फूटा व्यापारियों का गुस्सा

देहरादून। राज्य व्यापार मण्डल (रजि0) उत्तराखंड द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कॉरिडोर, मास्टर प्लान के नाम पर तोड़-फोड़ बस अड्डा, जहान्वी मार्किट शिफ्टिंग को लेकर व्यापारियों ने अपना विरोध दर्ज किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र चौटाला ने कहा की पिछले दो तीन वर्षो से शासन-प्रशासन द्वारा व्यापारियों में एक भय का माहौल बना दिया है ना जाने कब प्रशासन व्यापारियों को बेरोजगार कर देगा, किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ या विस्थापन होने पर अब व्यापारी चुप नहीं बैठेगा, यदि शासन प्रशासन ने अपनी नीति स्पष्ट नहीं की तों व्यापारी आने वाले सावन मेले एवम कुम्भ मेला में प्रशासन का सहयोग नहीं करेगा।

कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुमित अरोड़ा ने कहा की विकास के नाम पर विनाश नहीं होने देंगे, व्यापारियों कई वर्षो तक मेहनत कर अपना व्यापार स्थापित करता है अपना परिवार चलता है और वहीं शासन के जिम्मेदार अधिकारी चंद मिनटों में उसे उजाड़ने की योजना बना देते है जो व्यापारी हरकी पौड़ी में व्यापार कर रहा है वह अन्य स्थान पर व्यापार कैसे करेंगा, जो क्षेत्र पर्यटन विहीन है वहां व्यापारी किसी भी कीमत पर शिफ्ट नहीं होगा, शासन-प्रशासन को व्यापारियों की पीड़ा समझनीं चाहिए, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय प्रजापति व प्रदेश महामंत्री अतुल गोसाई ने कहा कि व युवा जिलाध्यक्ष विशाल गोस्वामी ने कहा की हरकी पौड़ी से अभी बस स्टैंड की दूरी 2 किलोमीटर है जगजीतपुर जाने से वो दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगी जो की स्थानीय जनता व श्रद्धालुओं के

सरकार व्यापारियों को उजाड़ने का षड्यंत्र कर रही है यहाँ के मूल निवासियों को उजाड़ा जा रहा है वहीं मेला लैंड पर बहारी क्षेत्रों से आये लोगों को संरक्षण दिया जा रहा अगर अभी भी सरकार नहीं जागी तों हरिद्वार से पूरे प्रदेश में निर्णायक आंदोलन होगा।

प्रदेश सयुंक्त महामंत्री दीपक गौनियाल साथ अन्याय है प्रदेश प्रचार सचिव गोकुल सिंह रावत व महानगर अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने कहा की यदि मेला प्रशासन व जिला प्रशासन ने मास्टर प्लान योजना में बदलाव नहीं किया तों व्यापारी और जोरदार तरीके से विरोध करेंगे, उक्रांद पूर्व लोक सभा प्रत्याशी मोहन सिंह असवाल ने कहा की यदि जल्द व्यापारियों की समस्या का सज्ञान नहीं लिया गया तों यूकेडी व्यापारीयों के साथ मिल कर देहरादून सचिवालय कूच करेगी, विरोध करने वालों में मुख्य रूप से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुमित अरोड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष भागवत अग्रवाल, तेजप्रकाश साहू, चंद शेखर गोस्वामी प्रदेश सचिव जसवंत बिस्ट, प्रदेश सचिव राजकांड पाल, हरकी पौड़ी अध्यक्ष गौरव अग्रवाल, नितिन शर्मा, गोकुल सिंह रावत, कनखल इकाई महामंत्री दिनेश कालरा, सोनल गर्ग, मधुर अरोड़ा, विनोद राठौर अध्यक्ष जमालपुर व्यापार मण्डल, बाबू लाल अध्यक्ष रावली मेहदूद व्यापार मण्डल, सागर प्रजापति, नितिन शर्मा, सौरभ अरोड़ा, रवि जैन, राकेश बिस्ट, रिक्की अरोड़ा, रवि शर्मा, नरेश चंयाना, मनोज वश्नोई, डॉ विष्णु दत्त वर्मा, मास्टर मुन्ना लाल, मोनू शर्मा, विकास शर्मा, विक्की अरोड़ा, नितीश मल्होत्रा, निखिल राजपाल, प्रदीप अग्रवाल, दीपक सिंघल, राजेश सिंघल, देव चौटाला, सागर बेनीवाल, पंकज सिंघल, मोनू शर्मा, राकेश बिस्ट आदि बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।

डेनमार्क की पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात, भारत-यूरोपीय संघ एफटीए का किया समर्थन

नई दिल्ली। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को टेलीफोन पर बात की। फ्रेडरिक्सन ने भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते का समर्थन किया। साथ ही भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने अपनी ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता के लिए डेनमार्क को शुभकामनाएं दीं। यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने में हमारी साझा रुचि पर भी चर्चा हुई।

एक बयान में कहा गया कि फ्रेडरिक्सन ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार

समझौते (एफटीए) को जल्द से जल्द पूरा करने और 2026 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए डेनमार्क के मजबूत समर्थन की पुष्टि की। पीएम मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान, स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया।

दशकों पुराने हैं दोनों देशों के संबंध

भारत और डेनमार्क के बीच दशकों पुराने मैत्रीपूर्ण और सहयोग भरे संबंध रहे हैं। दोनों देश 1949 से राजनयिक संबंध साझा करते हैं। भारत-डेनमार्क को एक विश्वसनीय भागीदार मानता है। दोनों देशों के बीच हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास जैसे क्षेत्रों में विशेष भागीदारी है। 28 सितंबर 2020 को आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को 'हरित रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाने जैसी महत्वपूर्ण साझेदारी की है।

डेनमार्क में भारतीय समुदाय द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, देश में लगभग 21,000 एनआरआई और पीआईओ रहते हैं। इस समुदाय में आईटी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वित्त और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर शामिल हैं।

अमेरिका बेनकाब! पाक के विदेश मंत्री का कबूलनामाः भारत को तीसरा पक्ष मंजूर नहीं

इस्लामाबाद। एक दुर्लभ और पहली सार्वजनिक स्वीकारोक्ति में, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने स्वीकार किया है कि भारत ने दोनों देशों के बीच विवादों पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का खंडन किया कि उन्हें कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए आमंत्रित किया गया था। डार ने कहा कि जब इस्लामाबाद ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के समक्ष ट्रंप के दावे को उठाया, तो अमेरिकी राजनयिक ने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली का हमेशा से यही रुख रहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी मामले 'पूरी तरह से द्विपक्षीय' हैं।

डार ने यह टिप्पणी अल-जज़ीरा पर एक बातचीत में की। डार ने कहा कि हमें तीसरे पक्ष की भागीदारी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि यह एक द्विपक्षीय मामला है। हमें द्विपक्षीय बातचीत से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन

बातचीत व्यापक होनी चाहिए, आतंकवाद, व्यापार, अर्थव्यवस्था, जम्मू-कश्मीर, सभी विषयों पर जिन पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि वाशिंगटन ने मई में एक युद्धविराम प्रस्ताव दिया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान किसी तटस्थ स्थान पर बातचीत करें। हालाँकि, 25 जुलाई को वाशिंगटन में रुबियो के साथ एक अनुवर्ती बैठक के दौरान, डार को बताया गया कि भारत इस योजना पर सहमत नहीं है।

उन्होंने कहा कि भारत ने दोहराया है कि यह एक द्विपक्षीय मामला है और वे किसी चीज़ की भीख नहीं मांग रहे हैं। दार ने कहा, 'भारत का कहना है कि यह एक द्विपक्षीय मामला है। हम किसी चीज़ की भीख नहीं मांग रहे हैं। हम एक शांतिप्रिय देश हैं और हमारा मानना ??है कि बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है; लेकिन बातचीत के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है।' उन्होंने दोहराया कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है।

झुक गया अमेरिका, भारतीय कृषि और डेयरी बाजारों में पहुँच की माँग छोड़ी! अब कह रहा है- बस हमारा चीज और कॉर्न खरीद लो

वाशिंगटन। भारत और अमेरिका के बीच ठंडी पड़ी व्यापार वार्ता एक बार फिर पटरी पर लौट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारी टैरिफ लगाने और वार्ता को निलंबित करने के कुछ ही हफ्तों बाद, वाशिंगटन से एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचा है ताकि बातचीत को पुनः शुरू किया जा सके। यह वार्ता सकारात्मक माहौल में शुरू भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस बार अमेरिका कुछ रियायतों के साथ आया है। अमेरिकी टीम अब भारत के विशाल कृषि और डेयरी बाजारों में व्यापक पहुंच की मांग नहीं कर रही। इसकी बजाय वह केवल भारत से अमेरिकी चीज़ और मक्का खरीदने की अपेक्षा कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उनका लक्ष्य भारत के संवेदनशील छोटे डेयरी किसानों से प्रतिस्पर्धा करना नहीं है, बल्कि उच्च श्रेणी के उत्पादों- जैसे प्रीमियम चीज़ को बेचने पर केंद्रित है। हालाँकि, अमेरिका की मक्का निर्यात योजना में अड़चनें हैं, क्योंकि उसका अधिकांश कॉर्न जेनिटिकली मॉडिफाइड है, जिसकी अनुमति भारत न तो आयात में देता है और न ही घरेलू स्तर पर खेती में। इसके अलावा, बिहार जैसे राज्यों में चुनावी परिदृश्य को देखते हुए इस पर राजनीतिक विरोध की संभावना भी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की यह 'झुकाव वाली' नीति उसके घरेलू कृषि संकट की देन है। चीन के साथ चल रहे व्यापार युद्ध ने अमेरिकी किसानों को गहरे आर्थिक नुकसान में डाल दिया है। चीन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा खरीदार था, अब ब्राज़ील जैसे विकल्पों की ओर रुख कर चुका है। ऐसे में अमेरिकी गोदाम बिना बिके सोयाबीन और कॉर्न से भर गए हैं। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन अब भारत जैसे बड़े बाज़ार के साथ समझौते की ओर लचीलापन दिखा रहा है।

उधर, नई दिल्ली में शुरू हुई वार्ता को विशेषज्ञों ने एक लंबी खींचतान करार दिया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का कहना है कि जब तक अमेरिका अतिरिक्त शुल्क, विशेषकर रूस से तेल आयात पर लगाई गई 25इ ड्यूटी को वापस नहीं लेता, तब तक कोई बड़ा ब्रेकथ्रू संभव नहीं है।

दूसरी ओर, देखा जाये तो भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता का पुनः आरंभ होना केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू-राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह इस तथ्य का प्रमाण है कि वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति कितनी मज़बूत हो चुकी है कि आज अमेरिका को बातचीत के लिए झुकना पड़ा है। ट्रंप प्रशासन की शुरुआती आक्रामक टैरिफ नीति वास्तव में अमेरिका के लिए ही उलटी साबित हुई। चीन के साथ चल रहे व्यापार युद्ध ने अमेरिकी किसानों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में भारत जैसा बड़ा और संभावनाओं से भरा बाजार अमेरिका के लिए अपरिहार्य बन गया है। यही कारण है कि पहले जो अमेरिका भारत से डेयरी और कृषि बाजार खोलने की मांग कर रहा था, वह अब प्रीमियम चीज़ और मक्का जैसे सीमित उत्पादों पर आकर अटक गया है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में एक रणनीतिक धैर्य का परिचय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न तो अमेरिकी दबाव के आगे झुकने का संदेश दिया और न ही अनावश्यक टकराव की राह अपनाई। 'स्वदेशी' और किसानों के साथ खड़े रहने का उनका संदेश देश के भीतर सशक्त राजनीतिक संकेत था, जबकि वैश्विक मंच पर इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत अमेरिकी दबाव के आगे अपने हितों से समझौता नहीं करेगा।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)